

नई दिल्ली
मंगलवार
06 अक्टूबर 2026
वर्ष: 13, अंक: 33
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु०

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhawnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

बिहार के सभी थानों में 30 दिनों के भीतर वीडियो...पेज-05

DELHIN/2014/58158

विद्यार्थी तकनीक को शक्ति और विवेक को...पेज-08

एक नजर

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों का किया खंडन

नई दिल्ली, एजेसी। चुनाव आयोग ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इन दावों का खंडन किया है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एकराज्य ढंग से प्रार्थ 6 में अरैध परिवर्तन किया है। आयोग ने कहा है कि जून 2025 के बिहार एसआईआर आदेश को आयोग की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इसे और इसके साथ ही संलग्न फॉर्म 6 घोषणा को भी बरकरार रखा था। जैसा कि उनके 26 सितंबर 2026 के प्रेस नोट में बताया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एस प्रोट को फेक्ट करके हुए चुनाव आयोग ने बयान नामक बताया है। आयोग ने कहा, 'बिहार में एसआईआर के लिए 24 जून 2025 को जारी आदेश आयोग की सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में बरकरार रखा है। ईसीआई ने 2026 के लिए प्रार्थ संख्या 120 दिनांक 26 सितंबर 2026 के बिंदु 1(iii) में कहा है, 'एसआईआर के लिए प्रार्थ 6 से संलग्न घोषणा को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार ने प्रार्थ 6 में अरैध और एकराज्य परिवर्तन किया है। यह भाजपा की मदद के लिए अपने पद का दुुरुपयोग करने का एक और प्रमाण है। उन्हें और लोकतंत्र पर इस अपराधिक हमले में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

शिक्षक भर्ती को लेकर राहुल ने
मप्र के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली, १ जून २०२१। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग-2 और वर्ग-3 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने भर्ती में पदवृद्धि के साथ आंदोलन कर रहे शिक्षक अग्रार्थियों को जारी नोटिस तत्काल वापस लेने, उनके प्रतिनिधियों से संवाद करने और दूसरे चरण की काउंसिलिंग जल्द शुरू कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गुंठ' कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के शिक्षक अग्रार्थियों ने वर्ग-2 और वर्ग-3 की भर्ती में पदवृद्धि का मुद्दा प्रमुखता से उनके सामने उठाया था। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से ही एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। इसके बावजूद शिक्षक भर्ती-2025 के तहत वर्ग-3 में केवल 13,089 और वर्ग-2 में 10,800 पदों पर भर्ती मिलीगी नई है। राहुल ने कहा कि प्रदेश के युवा अग्रार्थियों की मांग है कि शिक्षक भर्ती में शिविरों के अनुरूप पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और हजारों योग्य युवाओं को नियमित सरकारी रोजगार का अवसर मिलेगा। बड़ी संख्या में अग्रार्थियों ने चयन परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं। इनमें कई ऐसे अग्रार्थी भी हैं, जो लंबे समय से अतिथि शिक्षक के तौर पर सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और नियमित नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती में पदों की संख्या सीमित रहने से चयन परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कई अग्रार्थी भी नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति का इंतजार कर रहे कुछ अग्रार्थी अब निर्धारित आयु सीमा के करीब पहुंच रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक नायक अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली जिले के अंतर्गत आने वाले लोक नायक अस्पताल स्थित सच्ची वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को दी जा रही सेवाओं तथा शिकायतों के निस्तारण की पूरी व्यवस्था को विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और सेंटर की टीम से विभिन्न मामलों की प्रक्रिया, काउंसिलिंग, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मेडिकल सुविधा, अस्थायी आश्रय और मामलों पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हिंसा से पीड़ित प्रत्येक महिला और बच्ची को समयबद्ध, संवेदनशील एवं सम्मानजनक सहायता प्राथमिकता के साथ ही उच्च स्थिति में मदद के लिए वाली मॉडल बड़ा कवर पर पहुँचाने और सहायता चाहिए, पुरानी आवश्यक

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना हंड

आवाज़ अधिकार की



ज्ञानेश कुमार के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश से इनकार

● केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस



नई दिल्ली, ए.जे.सी। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निर्लंबित करने का एकरतफा अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि विशेष गहन पुरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े कई फैसले एकरतफा लिए जाने के आरोपों पर पहले चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों का जवाब मांगा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि नागरिकों के वोटिंग अधिकार खतरे में हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यह वोटर्स का 30 प्रतिशत है।

बंगाल में यह वोट्स का 25 प्रतिशत था अपोलेट
ट्रिब्यूनल के पास 16 लाख अपीलें लंबित हैं। उन
लोगों को पहले ही एक चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा
जा चुका है। अब एक और चुनाव आ गया है। मेनका
गुरुस्वामी ने कहा कि यह किसी खास राज्य तक

सोमतिम नहीं है। राज्य का इस्तेमाल सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर किया जा रहा है। हम हाल के चुनावों और चुनाव दिला रहे हैं। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय कमांडाओ और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ा मामला है। उस गैर-कानूनी काम को एक असंवैधानिक कानून के जरिए बचाया जा रहा है। इस तरह के पक्षपाती व्यवहार के लिए क्या सजा है? मैं खुद से यह सवाल पूछती हूँ। हम इस देश में आजाद और निष्पक्ष चुनावों के माहौल में बड़े हुए हैं। आज वे नहीं रहे। मैं इन मांगों पर कायम हूँ, हर एक मांग पर। यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ किया कि उच्चतम न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। यह बात उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपराधिक कार्यवाही करने

भाजपा ने उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए आठ नये चेहरे उतारे

● दो केन्द्रीय मंत्रियों को भी नहीं मिला टिकट

लखनऊ, एप्रैल ११। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की १० सीटों के लिए १६ अम्बुवर को होने वाले द्विपक्षीय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को अपने आठ प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिये जिनमें कार्यकाल पूरा कर रहे दो केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी और बीएल वामा सहित किसी निवर्तमान सदस्य का नाम नहीं है।

पाटी ने सर्वश्री धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, राम प्रताप सिंह चौहान और सुश्री प्रियंका सिंह रावत तथा श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। पाटी ने अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले विधान सभा चुनाव के मद्देनजर टिकट देने में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा है। उत्तर प्रदेश से भरी जा रही दस सीटों में नौ सीटें 25 नवंबर को रिक्त हो रही हैं। जबकि एक सीट श्री दिनेश शर्मा के सितंबर में इस्तीफे से रिक्त है। शर्मा

को पहले ही अंजमान एवं निकोबार का उप-राज्यपाल बनाया जा चुका है। उनका राज्य सभा का कार्यकाल भी नवंबर में ही समाप्त होने वाला था। भाजपा ने नवंबर में कार्यकाल पूरा कर रहे सात सदस्यों में से किसी को भी दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाया है। इनमें केन्द्रीय वर्मा हर्दीप सिंह पुरी और बीएल जर्जा के अलावा बृजलाल, नीरज शेखर, अरुण सिंह, सीमा द्विवेदी, गीता उर्फ चंद्र प्रथा शामिल हैं। भाजपा के नये प्रत्याशियों में श्रुति गंगवार बरेली शहरी सहकारी बैंक की अध्यक्ष हैं और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी हैं। श्री प्रकाश पाल भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तथा पार्टी की कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय ईकाई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। सुश्री प्रियंका सिंह रावत बाराबंकी से 16वीं लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। वह भाजपा के प्रमुख महिला चेहरों में शामिल हैं और संगठन में प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रही हैं।

**जीएसटी परिषद की बैठक
अब आठ अक्टूबर को होगी,
कई अहम बदलाव संभव**

नई दिल्ली, १ जून २०२३। माल एयरलाइंस सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विवादों में मामलों को सर्वोच्च न्यायालय जीएसटी अधिनियम के ५७वीं बैठक अब सात अक्टूबर की बजाय आठ अक्टूबर को खेती होगी। यह बैठक सुबह ११ बजे नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होगी की जाएगी। जीएसटी परिषद सचिवालय ने सोमवार को एक कार्यालय जापान में कहा कि 'परिस्थितियों' के कारण बैठक का तारीख बदल दी गई है। पहले यह बैठक सात अक्टूबर को होने वाली थी। जीएसटी परिषद की बैठक का तारीख में दूसरी बार बदलाव किया गया है। इससे पहले यह बैठक १२ सितंबर को होने वाली थी, लेकिन क्रिस स्मेलन २०२६ के लिए एसएक्सआर रिपोर्ट के लिए एक दिनांक दिया गया था। नयी दिल्ली में १२-१३ सितंबर को क्रिस स्मेलन हुआ था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद के बैठकों में पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और रिफंड की व्ययस्था के बदलाव पर चर्चा होने का अनुमान है।

संस्कृत के पास भारत की ज्ञान-परम्परा का एक विशाल भंडार है: राजनाथ सिंह

अयोध्या, एजेंसी। रक्षा मंत्री रामनाथ सिंह सोमवार को आश्विन शुक्ल अश्विन राणापोली श्री गुरु पर्व महामहोत्सव एवं संत सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आयोजित संत सम्मेलन एवं समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आश्विन परंपरा सनातन धर्म की बड़े जीवन की धारी है, जिसने सदियों से भारत की आध्यात्मिक चेतना को पोषित किया है। भारत की सभ्यता की एक बड़ी विशेषता यह रही है, कि यहाँ ज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा गया। ज्ञान को परम्परा बनाया गया।

उस परम्परा को संस्कार बनाया गया और फिर संस्कार को, शिक्षा के माध्यम से, समाज के व्यवहार में उतारा गया। शिक्षा किसी भी सभ्यता को रीढ़ होती है और जब शिक्षा का माध्यम संस्कृत जैसी देवभाषा हो, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आज जिस श्री नारायण संस्कृत महाविद्यालय को मैंने देखा, उसका स्थापना, 1912 में बाबा श्री केशवदास जी महाराज ने की थी। यह हर्ष का विषय है कि उस परम्परा को, आज तक यहाँ के संत, यहाँ के आचार्य निभा



रहे हैं। मैं इस अवसर पर, श्री महंत जी स्वामी भारत दास जी महाराज को हार्दिक से बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में ये आश्रम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। ये जो पूरी परम्परा है, इसका एक महत्वपूर्ण आधार संस्कृत है। संस्कृत को केवल एक भाषा नहीं समझा जा सकता। चाहे संस्कृत के पास भारत का इतिहास-परम्परा का एक विशाल भंडार हो, वेदों से लेकर उपनिषद तक, दर्शन, लेखन, व्याकरण तक, आयुर्वेद से लेकर

कांग्रेस ने तेज किया 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान

● 10 अक्टूबर से ब्लॉक स्तर पर रैली-पदयात्रा



बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अस्थिर न हो 'वोटे बचाओ, देश बचाओ' के नारे के साथ देशभर में व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने भी स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन एक-दो दिन का कार्यक्रम नहीं होगा और इसे लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनकी गिरफ्तारी और उनको खिलफाफ मुकदमा दर्ज होने तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि आज अक्टूबर तक इंडिया गठबंधन के घटक दल जिला स्तर पर सामूहिक प्रदर्शन और 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' आयोजित करेंगे। इसके बाद कांग्रेस 10 से 20 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर बाइक रैली, साइकिल रैली

गौर पदयात्राओं के जरिए अभियान चलाएगी। इन कार्यक्रमों में कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाता सूची और कथित वोट चोरी से जुड़े मुद्दों की जानकारी देने वाले पर्चे भी वितरित करेंगे। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक एक महीने का व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता 'वोट रक्षक' रूप में मतदाता सूची से हटाए गए करीब 15 लाख 13 करोड़ लोगों की पहचान के लिए प्रयास कर रहे हैं। गांवों में इन मतदाताओं के साथ चौपाल आयोजित कर उन्हें मतदाता सूची से जुड़े अधिकारों और कथित वोट चोरी के मुद्दे के प्रति जागरूक किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि अभियान का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि जिन पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल कराया जाए। गुणगोपाल ने बताया कि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ईडिया गठबंधन की बड़ी रैली आयोजित की जाएगी।

मुश्किल कामयाबी के बावजूद सोच बदलने की चुनौती

ज्योति मल्होत्रा

जब आप कमतर आंकी गई अपनी महिला धावकों को रेस ट्रैक पर सबसे श्रेष्ठ धावकों से आगे निकलते हुए देखते हैं – जैसा कि पिछले सप्ताह आइची-नागोया एशियाई खेलों में 4×400 मीटर फ़ाइनल में कोयंबटूर की विथ्या रामराज ने किया, पहले चीनी और फिर बहरीनी धावक को पछाड़कर, तब आप सोचते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होने का अर्थ क्या है। विथ्या ने तीसरे चक्र के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की प्राची चौधरी से बैटन लिया; तो कर्नाटक के कूर्ग की एमआर पूवम्मा ने दूसरा चक्र दौड़ा; उसने आगे यह बैटन बंदूक की आवाज़ पर दौड़ शुरू करने वाली हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गुमाड गांव की किरण पहल से पाया था। जब आप अपने सामने अद्भुत होता देखते हैं, तो तारीफ के वही पुराने तौर-तरीके आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। मसलन, मांसपेशियां, नसें, सालों का प्रशिक्षण और निरंतर तड़प जो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करती रहती है– ये सब मिलकर एक दौड़ में दिखे, जिसमें देश के अपेक्षकृत कम जाने जाते हिस्सों से आई चार महिलाएं दौड़ीं। भारत की बेटियां।

हमारी 'गोल्डन गर्ल्स'। विविधता में एकता। उत्तर-दक्षिण का मिलन और फ़र्क मिट गया। लेकिन तब क्या उन घिसी-पिटी मान्यताओं का असल में कोई अर्थ रहता है,जब ये महिला धावक –जो कुपोषण भरे बचपन, सामाजिक दबावों, गरीबी से जुझने में कड़ा संघर्ष, हर वक्त यौन उत्पीड़न की आशंका और छोटे गांव-छोटे शहरों की अव्यवस्था भरी जिंदगी के बीच भी अपने सपनों के लिए जुझती हैं और जीतती हैं? जहां एक ओर ये लड़कियां पिछले हफ्ते की शुरुआत में आइची-नागोया में अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रही थीं वहीं भारत की दूसरी बेटियां दिल्ली की सड़कों पर एक पार्क में हुए सामूहिक-बलात्कार के ख़िलाफ़ विरोध कर रही थीं। हममें से जो लोग 2012 की सर्दियों में हुए 'निर्भया' यौन उत्पीड़न के मामले को याद कर सकते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है मानो समय वहीं थमा हुआ है और हम हेरान हो रहे हैं–क्या वास्तव में कुछ बदला भी है? पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने कई तरह के टोटके आजमाए हैं, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से लेकर महिलाओं के बैंक खाते में पैसे डालने तक और उज्ज्वला गैस सिलेंडर जैसी सरकारी योजनाओं में बदलाव किए हैं जो महिलाओं को प्राथमिकता सुनिश्चित करती हैं। भले ही इनमें से कई योजनाओं का मकसद महिलाओं का एक राजनीतिक वोट



बैंक बनाना हो –लेकिन कम से कम उन्होंने कोशिश करना तो नहीं छोड़ा। तो फिर महिलाओं को ऐसा लगना क्यों जारी है कि उनकी कोई अहमियत नहीं? शायद इसलिए कि इन राजनीतिक कदमों के पीछे का उद्देश्य उनका नेकनीयत नहीं जितना होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के ध्येय के साथ कई शतें भी जुड़ी हैं –इनमें सबसे बड़ी समस्या है कोटा देने से पहले संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में विस्तार करना। महिला हॉकी गोलकीपर सविता पुनिया, जिन्होंने चीन के विरुद्ध फाइनल मैच में पेनल्टी स्ट्रोक रोककर टीम को 1-0 से गोल्ड मेडल जिताने में मदद की, हरियाणा के सिरसा की निवासी हैं। मई 2026 में सिरसा में जन्म के समय लिंगानुपात बहुत खराब रहा है – प्रति 1,000 लड़कों पर 883 लड़कियां। सरकार ने हाल ही में चार स्वास्थ्य अधिकारियों को बर्खास्त किया, उन पर गैर कानूनी तरीके से गर्भपात की

अनुमति देने का आरोप है। हरियाणा में यह खुला रहस्य है कि गर्भवती महिलाएं कन्या भ्रूण नष्ट करवाने पड़ोसी राज्य राजस्थान जाती हैं। (हरियाणा की सबसे खराब स्थिति वाले जिले गुरुग्राम व जींद हैं, जहां प्रति 1,000 लड़कों पर क्रमशः 863 और 872 लड़कियां हैं।) मिजोरम के कोलासिब की वासी लालरेम्सियामी हमारजोटे ने महिला हॉकी फ़ाइनल के 10वें मिनट में जीत दिलाते वाला गोल किया। झारखंड के सिमडेगा जिले के बड़कीचपार की रहने वाली सलीमा टेटे, खड़िया आदिवासी समुदाय से हैं और उन्होंने अपनी टीम की कप्तानी करते हुए शानदार जीत दिलाई। टेटे कहती हैं कि वह पूर्व महिला हॉकी कप्तान असुंटा लकड़ा को अपना आदर्श मानीं हैं, जिन्होंने जुलाई में हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह पर 'यौन उत्पीड़न और संस्थागत डराने-धमकाने' का आरोप लगाया था। सलीमा 'गोल्डन गर्ल्स' ने 44 साल में पहली बार गोल्ड मेडल जीता और 2028 ओलंपिक में अपनी जगह

पक्की की है। शायद सबसे मुश्किल सवाल अभी भी उनसे नहीं पूछे जा रहे जो सत्ता में हिस्सेदारी करना नहीं चाहते – आप ऐसा क्यों नहीं करते? महिलाओं के बारे में ऐसा क्या है, जिससे आप इतना डरते हैं? सर्वविदित है, लिंगानुपात में दक्षिणी राज्यों में केरल सबसे आगे है (वहां जन्म के समय प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,084 महिलाएं हैं), जबकि हरियाणा व पंजाब जैसे राज्यों में ये आंकड़ा कम है (क्रमशः प्रति 1,000 पुरुषों पर 898 व 924 महिलाएं), हालांकि इन तीनों राज्यों की आबादी करीब एक जैसी है – 3 करोड़। लेकिन, यहां दिलचस्प तथ्य है : केरल की मौजूदा विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या (140 में से 11) है जो पंजाब (117 में 13) और हरियाणा (90 में 13) की तुलना में कम है। हालांकि 1957 में हुए पहले चुनाव से ही केरल में महिला विधायक रही हैं – जब ईएमएस नंबूद्रीपाद के नेतृत्व में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई थी – लेकिन तब से लेकर

मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 13 दिवसीय 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' निकाली और नरें को ही राज्य का अपना मुख्य चुनावी एजेंडा घोषित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों जालंधर में यह घोषणा की, कि यदि पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है, तो 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को पूरी तरह से नशे के कारोबार से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने राज्य की भगवंत मान सरकार को 'आपदा' सरकार करार देते हुये यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध कारोबार को खुलेआम फलने-फूलने दिया है। जबकि 'आप' नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार पंजाब को बंदनाम कर रही है। 'आप' नेताओं ने गुजरात जैसे राज्यों के बंदरगाहों पर पकड़े जाने वाले भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का हवाला देते हुए केंद्र की सीमा सुरक्षा की विफलता पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर पंजाब के पूरे ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया जाएगा और नशे के व्यापारियों को जेल भेजा जाएगा। पंजाब में कथित तौर पर फैले नशा नेटवर्क को लेकर बनाई गई फ़िल्म 'उड़ता पंजाब' ने और भी इस विषय को प्रमुखता से कुछ इसतरह प्रचारित कर दिया गया देश का कृषि प्रमुख व भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के माध्यम से अपना अतुलनीय योगदान देने वाला देश का यहीं इकलौता राज्य है जो नशे में डूबा हुआ है।

नशे में उड़ता पंजाब: बद अच्छा बदनाम बुरा

तनवीर जाफ़री

पंजाब राज्य का भारतीय कृषि उत्पादन और देश की खाद्य सुरक्षा में सबसे अहम योगदान है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 1.5% हिस्सा होने के बावजूद, पंजाब को 'भारत का अन्न भंडार' और 'भारत की खाद्य टोकरी' कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा खुरीदे जाने वाले कुल गेहूँ का लगभग 46% हिस्सा अकेले पंजाब से आता है। केंद्रीय पूल में जमा होने वाले कुल चावल के सरकारी उपार्जन में भी पंजाब का लगभग 31% योगदान है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब 13 से 14 प्रतिशत का योगदान देता है। गेहूँ उत्पादन का लगभग 14% से 22% हिस्सा पंजाब में उगता है, जो इसे देश के शीर्ष उत्पादकों में बनाए रखता है। इसी तरह पंजाब देश के चावल उत्पादन का लगभग 10% से 11% हिस्सा पैदा करता है। भारत के कुल दूध उत्पादन में भी पंजाब लगभग 6.2% से 10% का योगदान देता है। इसी तरह देश के शहद उत्पादन में भी पंजाब का योगदान करीब 20% और मशरूम उत्पादन में रिकॉर्ड 48% है। पंजाब की यह सफलता उसकी फ़सल सघनता के कारण है, जो 186% से भी अधिक है। राज्य का लगभग 82% से 87% भूभाग खेती के अंतर्गत आता है, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 40% है। यही कारण है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब के किसान देश में अग्रणी बने हुए हैं और देश की भुखमरी मिटाने में सबसे आगे खड़े हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश कृषि उत्पादन से लेकर लंगर चलाने व ज़रूरतमंदों की मदद के लिये अग्रणी रहने वाले इस राज्य को विगत कुछ वर्षों से मात्र 'नशे ' को लेकर बदनाम करने की बड़ी साजिश रची जा रही है।

चूँकि पंजाब की 17 वीं विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में कराए जाने की पूरी संभावना इसीलिए चुनाव पूर्व विभिन्न राजनैतिक दल पंजाब में कथित तौर पर व्यास नशे की समस्या को एक प्रमुख राजनैतिक मुद्दा बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 13 दिवसीय 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' निकाली और नशे को ही राज्य का अपना मुख्य चुनावी एजेंडा घोषित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों जालंधर में यह घोषणा की, कि यदि पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है, तो 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को पूरी तरह से नशे के कारोबार से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने राज्य की भगवंत मान सरकार को 'आपदा' सरकार करार देते हुये यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने राज्य में सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध कारोबार को खुलेआम फलने-फूलने दिया है। जबकि 'आप' नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम कर रही है। 'आप' नेताओं ने गुजरात जैसे राज्यों के बंदरगाहों पर पकड़े जाने वाले भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का हवाला देते हुए केंद्र की सीमा सुरक्षा की विफलता पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर पंजाब के पूरे ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया जाएगा और नशे के व्यापारियों को जेल भेजा जाएगा। पंजाब में कथित तौर पर फैले नशा नेटवर्क को लेकर बनाई गई फ़िल्म 'उड़ता पंजाब' ने और भी इस विषय को प्रमुखता से कुछ इसतरह प्रचारित कर दिया गया देश का कृषि प्रमुख व भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के माध्यम से अपना अतुलनीय योगदान देने वाला देश का यही इकलौता राज्य है जो नशे में डूबा हुआ है। राजनीतिक दल भी एक-दूसरे को घेरने के लिए इस मुद्दे को कुछ इस तरह उछाल रहे हैं मानो पंजाब का हर दूसरा नागरिक नशेड़ी हो। जो



कि तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह ग़लत व निराधार है। जब हम राष्ट्रीय सन्दर्भ में पंजाब पर लगने वाले इसी 'लांछन' व काले धब्बे का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं तो हमें आंकड़ों के अनुसार यह पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य शराब की ख़पत में देश में सबसे आगे है। यहाँ लगभग 53% पुरुष और 24% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा राज्यों में भी शराब की खपत का प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। जबकि अफ़्रीम के सेवन में मिजोरम का नाम देश में सबसे आगे आता है। इसी तरह भांग व गांजे की चपेट में आने वाले सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम सर्वोपरि आता है। जबकि हर्शीश व चरस जैसे शेन के लिये हिमाचल के कसौल व मलाना जैसे इलाकों को सबसे प्रमुख माना जाता है। इस इलाक़े में तो लाखों की संख्या में विदेशी विशेषकर इस्पाईली नागरिक स्थायी रूप से यहाँ रहकर न केवल नशा करते हैं बल्कि इसके कारोबार में भी शरीक हैं। कसोल– मलाना का यह नेटवर्क गोवा तक फैला हुआ है। हॉ,पंजाब में अफ़्रीम की श्रेणी से जुड़े नशों का इस्तेमाल इस समय ज्यादा ज़रूर हो रहा है, जिनमें 'चिट्ठा' जोकि हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स का मिश्रण है, यह सबसे ख़तरनाक है। इसके अलावा परंपरिक तौर पर धुक्की व अफ़्रीम का चलन भी तेजी से बढ़ा है। परन्तु ज़वाह यह है कि जिस सिख बाहुल्य राज्य में जहाँ की बड़ी आबादी धूम्रपान को भी वर्जित समझती हो और कई शहरों,क्रस्वों व गांवों में तो बीड़ी,सिगरेट व तम्बाकू भी आसानी से उपलब्ध न हो उस समाज से जुड़े लोग आखिर नशे की गिरफ़्त में कैसे आ गये ?

दरअसल जो पंजाब कभी हरित क्रांति के कारण बहुत समृद्धि था वह पिछले कुछ दशकों में खेती से आमदनी घटने, उद्योगों की कमी और शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी बढ़ने के कारण निराशा में डूबता जा रहा है। दूसरी बात यह कि पंजाब के युवाओं में अमेरिका,कनाडा,यू के और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाने की भारी

होड़ लगी रहती है। परन्तु जिन युवाओं का वीज़ा नहीं लग पाता या जो असफल हो जाते हैं अथवा ठगे जाते हैं, वे मानसिक तनाव और अवसाद के कारण भी नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। जहाँ तक नशीली सामग्री की उपलब्धता का सवाल है तो पंजाब की पाकिस्तान के साथ क़रीब 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान से होने वाली ड्रास की तस्करी के लिए पंजाब एक 'ट्रॉजिट रूट' बन जाता है। हाल के दिनों में तो तस्करोँ द्वारा सीमा पार से ड्रोन के ज़रिए नशीले पदार्थों की सप्लाई करने के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से सीमा पार से आने वाली नशीले सामान की खेप को रोकने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार व उसके अधीनस्थ सुरक्षा बालों की है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में नशीले पदार्थों की कई बड़ी खेप देश के विभिन्न बंदरगाहों पर पकड़ी गई हैं। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के बीच ही देश के बंदरगाहों पर 11,311 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के ड्रग्स जब्त किए गए, जिनमें से अधिकांश मामले गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों पर सामने आए हैं। इनमें एक मुंदा बंदरगाह भी है। जिस का स्वामित्व और संचालन अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के पास है। इसके अलावा मुंबई के न्हावा शेवा पोर्ट, तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह, गुजरात के पीपावाव व कांडला बंदरगाह, तथा कोलकाता बंदरगाह से भी नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी जाती रही हैं। नि:संदेह पंजाब में फैली नशे की समस्या का राजनीतिकरण और इसका सनसनीखेज़ प्रदर्शन व प्रचार अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा हुआ है। अनेक फ़िल्मों और गानों में भी पंजाब को अक्सर 'नशे की राजधानी' के रूप में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। इससे पूरे राज्य और वहाँ के मेहनती युवाओं की एक वैश्विक छवि खराब हुई। वास्तव में पंजाब नशे को लेकर ' इस समय 'बद अच्छा बदनाम बुघ' की कहावत का शिकार है।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व कभी भी 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहा। इस बीच, पंजाब में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अलग तरह की दौड़ चल रही है। कांग्रेस पार्टी को नया राज्य अध्यक्ष मिल गया – परगत सिंह, जो पूर्व हॉकी ओलंपियन हैं। यह बदलाव कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी आसानी से व बिना किसी हंगामे के कर दिखाया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह 'राजा वडिं' का कद घटा दिया है।

वडिं अब लंदन में छुट्टियां मनाने जाएंगे। बाकी कांग्रेस पार्टी अपनी राह पर बढ़ चुकी है– आधार व उम्मीद, दोनों के साथ– दो भावनाएं, जो बीते हफ्ते राजनीति व खेल, दोनों ही क्षेत्रों में देखी गईं। गृह मंत्री अमित शाह ने जालंधर के प्राचीन देवी तालाब मंदिर में पूजा करने के बाद दूसरी भावना (उम्मीद) का जिक्र किया। चेहरे पर उम्मीद साफ़ छائی थी, उन्होंने बीते गुरुवार एक रैली में कहा कि हालांकि वह पंजाब में राजनीति पर बात करने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि अगर 'आप हमें एक बार सत्ता में लाते हैं', तो बीजेपी सूबे को नशे की समस्या से मुक्त कर देगी। कम भीड़ वाली रैली में उत्साह में नारे लगाए गए, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता इतनी कम भीड़ से खुश नहीं रहे होंगे, खासकर मार्च में हुई उनकी मोगा रैली की तुलना में। कुछ लोगों का कहना था कि शाह करीब आधे घंटे पहले ही पहुंच गए थे व लोग अभी आ ही रहे थे। पंजाब बीजेपी के नेता निजी तौर पर मानते हैं कि हाल के हफ्तों में पार्टी द्वारा सूबे में निकाली गई कई नशा-विरोधी यात्राएं–जो सभी जालंधर में आकर मिलीं–उनमें उम्मीद मुताबिक जन–उत्साह नहीं दिखा। जैसाकि मेरी सहयोगी नेहा सेंनी ने अमृतसर से खबर लिखी– कुछ यात्रा पड़वाँ पर तो सिर्फ 25-30 नशा-पीड़ित परिवारों की नुमाइश की गई, जिन्हें रैली के अग्रणी बीजेपी नेता लाए थे। अमित शाह के भाषण को ध्यान से सुनने वालों ने एक तीसरी बात पर ज़रूर गौर की होगी। उन्होंने पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला किया और कांग्रेस पार्टी पर भी – जो अभी भी देशभर में बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी और विरोधी है, भले ही वह कभी-कभी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है– लेकिन उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के विरोध में एक बार भी कुछ नहीं कहा। तो अब क्या होगा ? कौन सी पार्टी सबसे पहले जीत की रेखा पार करेगी ? सच तो यह कि बृहद राजनीतिक परिदृश्य में छोटा सा पंजाब इसलिए अहम है कि बीजेपी की प्रचंड ताकत का सामना वह कैसे करेगा, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं।

विचार

चार चरणों में पंचायती राज चुनाव से गांवों की सियासी तस्वीर होगी साफ

कातिलाल मांडोट

राजस्थान में लंबे समय से पंचायती राज चुनाव का इंतजार कर रहे ग्रामीण मतदाताओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव चार चरणों में 23 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर को होंगे। इनके परिणाम 20 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी तरह सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव चार चरणों में 25 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 6 नवंबर और 16 नवंबर को होंगे तथा मतदान के दिन ही परिणाम सामने आ जाएंगे। इसके बाद 25 नवंबर को जिला प्रमुख और 27 नवंबर को प्रधानों का चुनाव होगा। कोटा, श्रीगंगानगर, बारां और करौली जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव दिसंबर में होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकार नई योजनाओं की घोषणा, नए उद्घाटन और शिलान्यास नहीं कर सकेगी। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और तबादलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि पहले से स्वीकृत और प्रक्रिया में चल रहे विकास कार्य नियमों के अनुसार जारी रह सकेंगे। आचार संहिता का उद्देश्य यही है कि चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों अथवा घोषणाओं के जरिए मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके। इस बार का पंचायती राज चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव व्यापक स्तर पर एक साथ कराए जा रहे हैं। प्रदेश की 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। जिला परिषद के 1,403 और पंचायत समिति के 8,245 सदस्यों का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों से होगा, जबकि सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव मतपत्रों के जरिए होंगे। कुल मिलाकर करीब 1.69 लाख पंचायती राज प्रतिनिधियों के चुने जाने का रास्ता साफ हुआ है। 1.44 करोड़ से अधिक ग्रामीण मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे।

इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच के रूप में निर्वाचित होंगी। आरक्षण व्यवस्था ने ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लगातार बढ़ाया है और इस बार भी गांवों की सत्ता में महिलाओं की भूमिका निर्णायक रहने की संभावना है। अब सवाल है कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। इसका सीधा उत्तर चुनाव परिणाम आने से पहले देना उचित नहीं होगा, लेकिन हाल के राजनीतिक परिणामों और ग्रामीण मुद्दों को देखकर मुकाबले की तस्वीर समझी जा सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा ने राज्य की अधिकांश सीटों पर बढ़त बनाए रखी, हालांकि पिछली चुनाव में कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार किया। इसके बाद हुए उपचुनावों और स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी यह संकेत दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुकाबला एकतरफा नहीं है। इसलिए पंचायती राज चुनाव में संगठन, स्थानीय प्रत्याशी, जातीय और सामाजिक समीकरण तथा गांव के विकास कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ा आधार राज्य में सत्ता और उसका संगठनात्मक ढांचा माना जा सकता है। सरकार के स्तर पर किए गए विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति का असर ग्रामीण चुनाव में दिखाई दे सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास लंबे समय से गांवों में मौजूद स्थानीय संगठन, पुराने राजनीतिक संबंध और कई क्षेत्रों में मजबूत सामाजिक आधार हैं। यही कारण है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव विधानसभा या लोकसभा चुनावों से अलग परिणाम दे सकते हैं। यहां पार्टी के बड़े नेताओं से ज्यादा स्थानीय उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ और गांव में उसकी स्वीकार्यता प्रभाव डालती है। पंचायती राज चुनावों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ग्रामीण मतदाता स्थानीय समस्याओं को सीधे अपने मतदान से जोड़ता है। गांव में सड़क कैसी है, पेयजल की स्थिति क्या है, बिजली कितनी नियमित मिलती है, नाली और सफाई की व्यवस्था कैसी है, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं या नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं—ये सवाल चुनावी चर्चा के केंद्र में रहते हैं। केवल बड़े राजनीतिक मुद्दे ग्रामीण मतदाता के निर्णय को हमेशा तय नहीं करते। कई बार गांव की एक सड़क, पानी की टंकी, स्कूल का व्यवस्था या अस्पताल तक पहुंच का सवाल उम्मीदवार की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल देता है। इसलिए इस चुनाव में स्थानीय काम और व्यक्तिगत संपर्क का महत्व बहुत अधिक रहेगा। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में मतदाता यह भी देखेंगे कि उम्मीदवार जीतने के बाद गांव की आवाज जिला और पंचायत समिति स्तर तक कितनी मजबूती से पहुंचा सकता है।

एक नजर

पर्व-त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, पंडालों से जुलूस तक सुरक्षा के कड़े निर्देश



बक्सर,एजेंसी। आगामी पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को समाहरणालय में जिला पदाधिकारी साहि्ला की अध्यक्षता में विधि-व्यवस्था एवं पर्व-त्योहारों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य सहित संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पूजा समितियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। पूजा पंडालों में अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा, पर्याप्त प्रवेश-निकास, भीड़ नियंत्रण और आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया। जुलूस एवं शोभायात्रा के निर्धारित मार्ग और समय का पालन तथा आवश्यक अनुमति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित मानकों एवं समय-सीमा के अनुरूप ही कराने तथा अश्लील, अभद्र एवं आपत्तिजनक गीतों पर पूर्ण रोक लगाने को कहा गया। मूर्ति विसर्जन स्थलों एवं मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रकाश, बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाएं समय से पूरी करने का निर्देश दिया गया। संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, नियमित गश्त और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। आवश्यकता के अनुसार पलैंग मार्च कराने का भी निर्देश दिया गया। प्रमुख पूजा स्थलों, पंडालों एवं जुलूस मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा गया। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 'पुलिस दीदी' व्यवस्था सक्रिय रखने और जरूरत के अनुसार महिला पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक अथवा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री पर सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने आम लोगों से भाईचारा बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की।

कचरा फैलाने वाले रेस्टोरेंट व प्रतिष्ठानों को नगर परिषद का नोटिस



बक्सर। शहर में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नगर परिषद बक्सर ने सख्त कदम उठाया है। नगर परिषद प्रशासन ने सड़क, नाली और फुटपाथ पर कचरा फेंकने वाले प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया है। नगर परिषद के अनुसार नियमित रूप से सफाई और कूड़ा उठाव के बावजूद कई दुकानों, रेस्टोरेंटों और भवनों के सामने दोबारा कचरा फेंक दिया जाता है। इससे शहर की स्वच्छता प्रभावित होने के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।

नोटिस पाने वालों में नमक फैमिली रेस्टोरेंट, पार्क व्यू फैमिली रेस्टोरेंट एंड बैकेट हॉल तथा जमुना चौक स्थित कोलकाता रॉयल बिरयानी हाउस शामिल हैं। नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-6174/2023 में पारित न्यायादेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन के लिए मोबाइल कोर्ट का गठन किया गया है। टीम शहरी क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर रही है। सड़क, नाली, फुटपाथ या सरकारी भूमि पर कचरा फैलाना और कचरा जलाना प्रतिबंधित है। नोटिस में प्रतिष्ठान संचालकों और भवन स्वामियों को अपने परिसर के सामने कचरा नहीं फेंकने तथा स्वयं कूड़ेदान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2019 और बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मैथिली में अनुवाद क्षमता बढ़ाने को पांच दिवसीय कार्यशाला शुरू

सुपौल। जिले के निर्मली अनुमंडल स्थित हरि प्रसाद साह महाविद्यालय में सोमवार से पांच दिवसीय अनुवाद कौशल विकास कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का आयोजन हरि प्रसाद साह महाविद्यालय और राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, मैसूर के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। पांच से नौ अक्टूबर तक चलने वाली कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय भाषाओं, विशेषकर मैथिली में अनुवाद क्षमता को विकसित करना है। कार्यशाला का उद्घाटन समन्वयक डॉ. रामभू कुमार सिंह और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. उपेन्द्र पंडित ने किया। वक्ताओं ने कहा कि अनुवाद केवल शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ज्ञान, विचार और संस्कृति को एक-दूसरे तक पहुंचाया जाता है। स्थानीय समन्वयक डॉ. अतुलेश्वर झा ने कार्यशाला के उद्देश्य और इसकी उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। पहले दिन डॉ. अतुलेश्वर झा, विजय शंकर और तीकांशू हाशमी ने अलग-अलग विषयों पर सत्र लिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भाषाई चुनौतियों, उचित शब्द चयन और अनुवाद की व्यावहारिक तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में महाविद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी भाग ले रहे हैं।

बिहार के सभी थानों में 30 दिनों के भीतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू करने का निर्देश

कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू करने का निर्देश

पटना,एजेंसी। बिहार सरकार के गृह विभाग में मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति को लेकर सोमवार को समीक्षात्मक बैठक हुई। गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने राज्य के सभी थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अगले 30 दिनों के भीतर सक्रिय कराने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू होने से थानों और वरीय पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बेहतर होगा तथा जरूरी मामलों में त्वरित संवाद स्थापित किया जा सकेगा।

बैठक में लंबित फोरेंसिक जांच रिपोर्ट से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट लंबित रहने के कारण अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संबंधित पदाधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रधान सचिव ने स्पीडी ट्रायल के मामलों में संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मामलों का शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर समन्वय के साथ कार्रवाई की जाए, ताकि मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। बैठक में विभिन्न आयोगों की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा और सुचारु संचालन को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रधान सचिव ने कहा कि पुलिस मुख्यालय जिला



प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर इन परीक्षाओं की मिशन मोड में निगरानी करे। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की आवाजाही और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। परीक्षा के दिन संबंधित शहरों में यातायात व्यवस्था को विशेष रूप से सुचारु रखने का निर्देश दिया गया, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो और आम नागरिकों के आवागमन पर भी अनावश्यक प्रभाव न पड़े। प्रधान सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन

अवैध नशे के खिलाफ भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 52 ग्राम स्मैक और गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

भागलपुर। जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए भागलपुर पुलिस ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘स्वस्थ युवा, स्वस्थ भागलपुर’ के तहत लोदीपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।

पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक और गांजे के साथ एक शांतिर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भागलपुर के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लोदीपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर-बिशनपुर जिच्छो गांव में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि जब पुलिस टीम चिह्नित स्थान सैदपुर-बिशनपुर जिच्छो गांव पहुंची, तो पुलिस बलों को देखकर एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा। मौके पर मुस्तैद सशस्त्र पुलिस बलों ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और खदेड़कर उसे दबोच लिया। फेसडे गैंग आरोपी की पहचान सिंटू कुमार मंडल (पिता- स्वर्गीय परमेश्वर मंडल), निवासी सैदपुर-बिशनपुर जिच्छो, थाना लोदीपुर, भागलपुर के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा ली गई तलाशी में आरोपी के पास से 52 ग्राम स्मैक और 8 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। प्रेस वार्ता में डीएसपी ने स्पष्ट किया कि आरोपी को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की जा रही है, ताकि नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरों को बेनकाब किया जा सके। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी साफ किया कि बरामदगी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, हालांकि मामले में अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के अवैध नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

वर्षों से रास्ते के लिए भटक रहे दलित परिवार, बच्चों की पढ़ाई और मरीजों का इलाज प्रभावित

सुपौल,एजेंसी। जिले के राधोपुर थाना क्षेत्र के राधोपुर पंचायत स्थित वार्ड संख्या-02 में रास्ते की समस्या को लेकर दर्जनों दलित परिवार वर्षों से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके घरों तक पहुंचने और आसपास के लोगों के आवागमन के लिए वर्षों से इस्तेमाल किए जा रहे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। रास्ता बंद होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के आवागमन के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और मरीजों के इलाज में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवारों के अनुसार, रास्ता बाधित होने से स्कूली बच्चों को आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। खासकर बारिश के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है। वहीं, किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने या अचानक आपात स्थिति उत्पन्न होने पर उसे अस्पताल तक पहुंचाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार मरीजों को चारपाई या अन्य साधनों से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, जिसके कारण इलाज में भी विलंब होने की आशंका बनी रहती है।

पीड़ित सत्य नारायण पासवान सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उक्त रास्ते का इस्तेमाल करीब 50 से 60 वर्षों से लगातार किया जाता रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक इस मार्ग से करीब 40 से 45 परिवारों का आवागमन होता है। उनका कहना है कि रास्ते की समस्या कोई नई नहीं है। इसे लेकर ग्रामीण पिछले कई वर्षों से संबंधित



अधिकारियों और प्रशासनिक कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं तथा कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। इसके बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद होने से सबसे अधिक परेशानी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हो रही है। बच्चों को स्कूल भेजने, बुजुर्गों को अस्पताल ले जाने तथा रोजमर्रा के जरूरी कार्यों के लिए मुख्य मार्ग तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थल की जांच कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेने की मांग की है।

इस संबंध में पीड़ित परिवारों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर मामले की जांच कराने तथा वर्षों से बंद रास्ते को शीघ्र चालू कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कहा कि यह रास्ता उनके लिए महज आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर रास्ते की समस्या का स्थायी समाधान कराने और प्रभावित परिवारों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

सीवान,एजेंसी। पाइपलाइन के जरिये गैस

आपूर्ति के विस्तार के बीच एलपीजी सिलेंडर की सुविधा बंद होने की आशंका को लेकर एलपीजी वितरकों ने सोमवार को शहर के जेपी चौक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (इंडिया) के आह्वान पर जिले के करीब 48 गैस वितरकों ने कैंडल मार्च में शामिल होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। वितरकों ने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे पाइपलाइन गैस लें या एलपीजी सिलेंडर। गैस वितरक मोहम्मद खालिद ने कहा कि शहर और मोहल्लों में पाइपलाइन बिछायी जा रही है। सरकार की ओर से पाइपलाइन गैस के विस्तार की बात कही जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि पाइपलाइन पहुंचते ही संबंधित इलाके के लोगों के एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिये जाएं।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता का ‘राइट टू चॉइस’ बरकरार रहना चाहिए। जिसे पाइपलाइन गैस लेना है, वह ले और जिसे सिलेंडर की सुविधा चाहिए, उसे सिलेंडर मिलता रहे। उन्होंने कहा कि पिछले करीब सात वर्षों में डीजल और परिवहन लागत में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन एलपीजी वितरकों के कमीशन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में होम डिलीवरी चार्ज बढ़ाकर 75 रुपये करने की मांग की जा रही है। मोहम्मद खालिद ने बताया कि सरकार की ओर से एलपीजी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कार्रवाई जा रही है। यदि अनिवार्य निरीक्षण जैसी सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित है, तो अनिवार्य

अनंत सिंह की नाराजगी पर बोले ललन सिंह, नीरज कुमार के खिलाफ कार्रवाई न करना थी चूक

पटना। बिहार विधान परिषद की शिक्षक-स्नातक सीट को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच बाहुबली विधायक अनंत सिंह की नाराजगी दूर करने की कोशिश तेज हो गई है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को उनसे बातचीत के लिए लगाया। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ललन सिंह ने बताया कि अनंत सिंह ने उनके सामने कई शिकायतें रखी हैं।

ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत में यह भी स्वीकार किया कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह के खिलाफ चलाए गए अभियान में नीरज कुमार शामिल थे और उस समय पार्टी नेतृत्व की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह का कहना है कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब जदयू के कई नेताओं ने उनसे सरकार के समर्थन का आग्रह किया था। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति सम्मान के कारण सरकार का समर्थन किया। अनंत सिंह का तर्क है कि जब उन्होंने संकट के समय सरकार का साथ दिया तो बाद में उनके खिलाफ चुनाव अभियान चलाए जाने पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार के समर्थन के बाद अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से

मुलाकात की थी। उस दौरान उन्हें मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। ललन सिंह के अनुसार, इस बातचीत के दौरान संजय झा समेत कई नेता मौजूद थे। इसके बाद अनंत सिंह ने मोकामा से चुनाव लड़ा। अनंत सिंह की प्रमुख शिकायत विधानसभा चुनाव के लिए लगाया। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ललन सिंह ने बताया कि अनंत सिंह ने उनके सामने कई शिकायतें रखी हैं। ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत में यह भी स्वीकार किया कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह के खिलाफ चलाए गए अभियान में नीरज कुमार शामिल थे और उस समय पार्टी नेतृत्व की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार ने अनंत सिंह के खिलाफ अभियान चलाया था और उस समय प्रदेश नेतृत्व की ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कार्रवाई नहीं किया जाना प्रदेश नेतृत्व की चूक थी। ललन सिंह के मुताबिक, अनंत सिंह ने पार्टी की एक बैठक में भी यह मामला उठाया था। उन्होंने बैठक में मौजूद नेताओं से सवाल किया था कि क्या नीरज कुमार ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया था या नहीं। अनंत सिंह का कहना था कि जो व्यक्ति उनके खिलाफ चुनाव में अभियान चलाता रहा, उसके लिए वह वोट मांगने की स्थिति में कैसे रह सकते हैं।

पाइपलाइन गैस आने पर सिलेंडर बंद न हो, उपभोक्ताओं को मिले पसंद का अधिकार



ई-केवाईसी के लिए भी प्रति उपभोक्ता 236 रुपये वितरकों को मिलना चाहिए। उन्होंने तेल कंपनियों द्वारा वितरकों को उनकी मांग से अलग सामान भेजे जाने का भी विरोध किया। खालिद के अनुसार, 19 किलोग्राम और पांच किलोग्राम के सिलेंडर, पाइप, होज जड़ण समेत अन्य सामान बिना ऑर्डर के जबन नहीं भेजे जाने चाहिए। वितरक ने जिस सामान की मांग की है, उसी के अनुरूप आपूर्ति होनी चाहिए। एसोसिएशन के अनुसार आंदोलन के आगेले

मॉडल ब्लॉक भवन की गुणवत्ता पर सवाल के बीच 50 लाख रंगदारी मांगने का आरोप

सीवान,एजेंसी। जिले के आंदर प्रखंड में निर्माणाधीन मॉडल ब्लॉक भवन को लेकर एक ओर जहां निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए दरौली के विधायक विष्णु देव पासवान ने भवन निर्माण विभाग से तकनीकी जांच की मांग की है, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य से जुड़े विवेक कुमार सिंह ने निर्माण स्थल पर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने, काम बंद कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए आंदर थाने में शिकायत दी है।

मामले में पुलिस द्वारा दो लोगों को हिरासत में लिये जाने की बात सामने आयी है। विधायक विष्णु देव पासवान ने 16 सितंबर को भवन निर्माण विभाग के सचिव को पत्र भेजकर आंदर में निर्माणाधीन मॉडल ब्लॉक भवन की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की थी। पत्र में उन्होंने कहा था कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि निर्माण कार्य की शर्तों, स्वीकृत प्राक्कलन, निर्धारित मानकों एवं तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है। विधायक ने सक्षम तकनीकी टीम से स्थल निरीक्षण कराने तथा भवन के कॉलम एवं अन्य महत्वपूर्ण संरचनात्मक हिस्सों की मजबूती की जांच कराने का आग्रह किया था। आवश्यकता के अनुसार सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण और सैंपल लेने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने की मांग भी की गयी थी। विधायक ने संबंधित संवेदक द्वारा पिछले पांच वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों की भी विशेष जांच कराने को कहा था। उनका कहना था कि जांच में अनियमितता मिलने पर संबंधित के

खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विधायक की ओर से इससे पूर्व भी निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विभाग को शिकायत किये जाने की बात सामने आयी है। इसी बीच बेलोर निवासी विवेक कुमार सिंह ने 5 अक्टूबर को आंदर थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया कि मझबलिया निवासी अमित कुमार पासवान और भवराजपुर निवासी साहेब हुसैन निर्माणाधीन कार्यस्थल पर पहुंचे और उनसे 50 लाख रुपये रंगदारी की मांग की। आरोप है कि राशि नहीं देने पर काम बंद करने और जान से मारने की धमकी दी गयी। शिकायतकर्ता के अनुसार, साहेब हुसैन ने फोन कर करीब 15 युवकों को मौके पर बुला लिया और हथियार के साथ उसे घेर लिया। आवेदन के मुताबिक, इसी दौरान डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद अधिकारी लोग भाग गये और अमित पासवान व साहेब हुसैन को पुलिस अपने साथ थाने ले गयी।शिकायतकर्ता ने पूर्व में भी अपने ऊपर हमले की शिकायत किये जाने तथा आंदर थाना कांड संख्या 285/26, दिनांक 22 सितंबर 2026 दर्ज होने का उल्लेख किया है। शिकायत में विधायक के स्तर से निर्माण राशि के तीन प्रतिशत भुगतान का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। विधायक विष्णु देव पासवान ने कहा कि गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं हो रहा था। इस वजह से विभाग ने उचित से शिकायत की गई है। ठेकेदार द्वारा मैनेज करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इन्कार कर दिया। हर हाल में गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। सोमवार को ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा था।

एक नजर

धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का भारत पर 20 और वेस्टइंडीज पर 10 प्रतिशत जुर्माना



नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज पर शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टी-20 के तीन मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मुकाबले में धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए भारत पर मैच फीस का 20 प्रतिशत, जबकि वेस्टइंडीज पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भारत प्रतिभारित ओवर गति से चार ओवर और वेस्टइंडीज दो ओवर पीछे रहा। दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए प्रस्तावित सजा को मान लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। आईसीसी अंतरराष्ट्रीय मैच रेफरी पैनल के प्रकाश भट्ट ने ये प्रतिबंध लगाए। मैदान पर अंपायर जयरामन मदनगोपाल और सैम नोगाज्स्की, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद तथा चौथे अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने धीमी ओवर गति के आरोप लगाए थे।

वेस्टइंडीज ने तीसरे एकदिवसीय मुकाबले से पहले तीन मैचों की श्रृंखला 0-2 से गंवा दी थी, लेकिन न्यू चंडीगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भारत दौरे के एकदिवसीय चरण का शानदार अंत किया। शाई होप ने नाबाद 162 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वेस्टइंडीज ने 352 रन के लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज दर्ज किया। अब दोनों टीमों पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जिसका पहला मुकाबला 6 अक्टूबर से खेला जाएगा।

हॉकी इंडिया लीग के बाद लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए नई टीम तैयार करना हमारा लक्ष्य : फ्रेग फुल्टन



नई दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दो दिन पहले आइची-नागोया एशियाई खेलों में मलेशिया को फाइनल में 5-1 से हराकर अपने एशियाई खेलों के खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत के साथ हरमनप्रीत सिंह की अगुआई वाली भारतीय टीम ने लॉस एंजिल्स-2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई भी कर लिया। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम के मुख्य कोच फ्रेग फुल्टन ने साई मीडिया से विशेष बातचीत में कहा कि लॉस एंजिल्स ओलंपिक अब ज्यादा दूर नहीं है और हॉकी इंडिया लीग के बाद उन्हें नई टीम तैयार करने पर काम करना होगा। इसमें टीम में अधिक युवा खिलाड़ियों को शामिल कर अनुभव और युवा जोश के बीच बेहतर संतुलन बनाने पर जोर रहेगा। फुल्टन ने कहा, ‘लॉस एंजिल्स 2028 दो साल के भीतर है। ऐसा लगता है कि अभी काफी समय है, लेकिन यह समय बहुत जल्दी आ जाता है। फिलहाल हम सही कार्यक्रम और सही योजना तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह तय करना है कि दो साल पहले, एक साल पहले और छह महीने पहले हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए और उसी के अनुसार योजना बनानी है। हां, मुझे लगता है कि हर टीम में अनुभव और युवाओं के अपने चरण होते हैं। हमारे पास इस समय अनुभवी खिलाड़ियों का एक अच्छा समूह है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे पास कुछ युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन भारतीय ए टीम और मजबूत अंडर-21 टीम में हमारे पास काफी युवा प्रतिभा है, जो शानदार है। इसलिए अगले दो-तीन महीनों में, मेरा मानना ​​है कि हॉकी इंडिया लीग के बाद हम अपनी पूरी प्रतिभा पर नजर डालेंगे, नई टीम चुनेंगे और वहां से नए सिरे से शुरूआत करेंगे।’ यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एशियाई खेलों में कुल पांचवां स्वर्ण पदक है। इससे पहले टीम ने 1966 बैकॉक, 1998 बैकॉक, 2014 ईंचियोन और 2022 हांगझोउ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।

1996 और 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कर चुके फुल्टन ने लगातार दो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने को विशेष उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, ‘व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये एशियाई खेल बहुत अनोखे रहे। यह पिछले एशियाई खेलों से बहुत अलग था, क्योंकि हम यहां अन्य स्पर्धाओं और खिलाड़ियों से एक तरह से अलग थे। यहां कोई तथाकथित खेल गांव नहीं था, लेकिन साथ ही हमारी अपनी दिनचर्या थी। हम मैदान पर जाते थे, खेलते थे, वापस आते थे और सब कुछ उसी तरह चलता था, लेकिन हांगझोउ में पहला स्वर्ण पदक जीतना बहुत खास था। लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर उसका बचाव करना हमेशा विशेष होता है।’ भारत ने गिफ्ट प्रीक्वलर लीग स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को मैच के आखिरी क्षणों में 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने एक समय 3-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया था। हरमनप्रीत सिंह ने पांचवें और 13वें मिनट में तथा सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में गोल कर भारत को 3-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद अबू महमूद ने 30वें, हन्नान शाहिद ने 45वें और वहीद राणा ने 49वें मिनट में गोल कर पाकिस्तान को बराबरी पर ला दिया। अभिषेक ने मैच के अंतिम मिनट में गोल कर भारत को फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर फुल्टन ने कहा, ‘सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। हमारा पहला हाफ वास्तव में बहुत अच्छा रहा, लेकिन तीसरा क्वार्टर मुश्किल था। पाकिस्तान ऐसी टीम है कि अगर आप उन्हें कोई भी मुफ्त अवसर देते हैं, तो वे उसे भुनाते हैं और वे एक शानदार टीम हैं, उन्होंने यह दिखाया भी। उन्होंने अच्छी वापसी की और 3-0 से 3-3 तक पहुंचकर हम पर काफी दबाव बनाया। उस दौरान भी हमारे पास कुछ अच्छे मौके थे, लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं कर सके, गोल नहीं कर सके। फिर हमने आखिरी मिनट में गोल करने का रास्ता निकाला और चौथा गोल किया, जिसने हमें फाइनल में पहुंचने में मदद की। आइची-नागोया में भारतीय पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों का स्वर्ण पदक जीतना एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार हुआ है।

वैभव प्रतिभाशाली और शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन अवसर के लिए इंतजार करना होगा: गौतम गंभीर

नई दिल्ली,एजेंसी। लगातार दो बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीत चुकी भारतीय टीम घरेलू सत्र की शुरुआत दो बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से करेगी। सीरीज से पहले भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ काम करने के अनुभव और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ हुई बातचीत को लेकर अपनी बात रखी। जियोस्टार के कार्यक्रम ‘फॉलो द ब्लूज: गौतम गंभीर अनफिल्टर्ड’ में गंभीर ने श्रेयस अय्यर की नेतृत्व क्षमता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अय्यर को सबसे बड़ी खूबी उनकी निस्वार्थ भावना है।

गंभीर ने कहा, ‘श्रेयस के साथ मेरा पहला अनुभव तब हुआ जब मैं 2024 में केकेआर में गया था, जहां वह कप्तानी कर रहे थे। श्रेयस के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि वह कई बार अपनी बल्लेबाजी की स्थिति छोड़ने के लिए तैयार रहते थे। वह इतने लचीले थे कि अगर कोई और खिलाड़ी उनसे ऊपर बल्लेबाजी करने जाता था तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं थी। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कप्तान, जो शायद आपकी टीम का मुख्य बल्लेबाज भी हो, टीम के हित में अपनी बल्लेबाजी की स्थिति किसी और के लिए छोड़ दे, चाहे वह किसी और खिलाड़ी को प्रभाव पैदा करने का मौका देने के लिए हो या बाएं-दाएं बल्लेबाजी संयोजन के दृष्टिकोण से। तभी मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छे नेता की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खूबी यह है कि आप कितने निस्वार्थ हैं। उन्होंने आगे कहा,’ श्रेयस में यह खूबी है और कप्तान के रूप में अपने



आगे के सफर में वह इसे एक बड़ी ताकत के रूप में लेकर चल सकते हैं। आप मेहनती हो सकते हैं, अनुशासित हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप निस्वार्थ नहीं हैं तो बाकी सभी चीजें बेकार हो जाती हैं। श्रेयस में ये सभी खूबियां हैं और इसके ऊपर उनमें वह निस्वार्थ भावना भी है। वैभव सूर्यवंशी को लेकर हुई बातचीत के बारे में गंभीर ने कहा कि युवा खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण उन्हें अपने अवसर का इंतजार करना पड़ सकता है। गंभीर ने कहा, ‘यह मेरे लिए भी एक नया अनुभव था। हां, वह शानदार फॉर्म में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कभी-कभी लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की वजह से उन्हें अपने अवसर के लिए इंतजार करना होगा। और एक और बात है, सोशल मीडिया या बाहर का

शोर प्लेइंग इलेवन तय नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रेसिंग रूम में कौन, या कोच और कप्तान किसे लगता है कि वह हमें मैच जिता सकता है, या सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन क्या है, और कौन इतने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘क्योंकि अगर वैभव आज खेलते हैं तो मेरे और उस खिलाड़ी के बीच एक मुश्किल बातचीत होगी जिसे हम बाहर रखते हैं, चाहे वह अभिषेक हों या संजू। इसलिए हम अचानक उस संयोजन को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसने पिछले डेढ़ या दो वर्षों में इतना प्रभाव पैदा किया है और तीन या चार असफलताओं के बाद उन्हें बाहर कर ऐसे युवा खिलाड़ी को मौका दे दें जो बेहद प्रतिभाशाली है और बहुत अच्छी फॉर्म में भी है। इसलिए कभी-कभी आपको अपने अवसर के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि हम उस ड्रेसिंग रूम में सुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं।’

एशियाई खेलों में भारतीय पहलवानों ने किया शानदार प्रदर्शन, छह पदकों के साथ रहा सर्वश्रेष्ठ परिणाम

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती दल ने जापान के आइची-नागोया में हाल ही में समाप्त हुए 20वें एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए छह पदक जीते। भारत ने दो स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक अपने नाम किए। जापान में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में यह भारत का एशियाई खेलों में अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ कुश्ती प्रदर्शन है। इससे बेहतर प्रदर्शन भारत ने केवल 1962 के एशियाई खेलों में किया था, जहां भारतीय पहलवानों ने कुल 12 पदक जीते थे। भारत ने 18 में से 15 बार वर्गों में पहलवान उतारे और फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन तथा महिला कुश्ती तीनों वर्गों में पदक हासिल किए। भारतीय पहलवानों ने इस दौरान ओलंपिक चैंपियन, मौजूदा विश्व चैंपियन और विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज पहलवानों को भी मात दी।

65 किग्रा फ्रीस्टाइल में सुजीत कलकल ने पदार्पण करते हुए स्वर्ण पदक जीता। विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद सुजीत ने सेमीफाइनल में जापान के 2024 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कियोका कोटारो को 3-3 की बराबरी के बाद मानदंड के आधार पर

हराया। फाइनल में उन्होंने ताजिकिस्तान के अब्दुलमाजिद कुडिएव को 10-9 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। वह 65 किग्रा फ्रीस्टाइल में एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने वाले तीसरे भारतीय बने। 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में अमन सहरावत ने भी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। विश्व रैंकिंग में 32वें स्थान पर मौजूद अमन ने फाइनल में उत्तर कोरिया के विश्व नंबर एक और 2025 विश्व चैंपियन चौंग सोंग हान को 11-7 से हराया। यह इस भार वर्ग में एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। ग्रीको-रोमन के 97 किग्रा वर्ग में नितेश ने रजत पदक जीता। वह 64 साल बाद एशियाई खेलों के ग्रीको-रोमन फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने। उनसे पहले 1962 में मारुति माने ने 97 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था। नितेश ने सेमीफाइनल मुकाबला दो मिनट के भीतर 9-0 से जीता था। महिला 53 किग्रा वर्ग में विश्व नंबर एक अंतिम पंचाल ने रजत पदक हासिल किया। उन्होंने फाइनल में पहुंचने के दौरान पांचवीं रैंक की पहलवान को हराया और दो मुकाबले बिना कोई अंक गंवाए जीते। यह 2023 में जीते कांस्य पदक के बाद उनके प्रदर्शन में सुधार है।

पुर्तगाल ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर नेशंस लीग क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

पोर्टो,एजेंसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो

के बिना खेल रहे मौजूदा चैंपियन पुर्तगाल ने रविवार रात नेशंस लीग में नॉर्वे को 2-1 से हराकर मार्च में होने वाले क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। पुर्तगाल ने प्रतियोगिता में लगातार चार जीत दर्ज करते हुए गुप एप में शीर्ष दो में स्थान सुनिश्चित कर लिया है। पुर्तगाल की ओर से गोंसालो रामोस ने मैच खत्म होने से 11 मिनट पहले निर्णायक गोल किया। इस जीत के बाद पुर्तगाल दूसरे स्थान पर मौजूद डेनमार्क से छह अंक आगे हो गया है। डेनमार्क ने कार्डिफ में वेल्स को 1-0 से हराया। रोनाल्डो पिछले सप्ताह कोच जॉर्ज जीसस के साथ विवाद के बाद टीम से अलग हो गए थे। उनके बिना भी पुर्तगाल ने गुरुवार को डेनमार्क के खिलाफ जीत दर्ज की थी और अब घरेलू मैदान पर नॉर्वे को हराकर अपनी जीत की लय कायम रखी। नॉर्वे ने 36वें मिनट में बढ़त बनाई। सेंटर-बैक क्रिस्टोफर एंडर ने पेनल्टी क्षेत्र के बाहर से शानदार हाफ-वॉली लगाकर गेंद को गोल में पहुंचाया। हालांकि, दो मिनट बाद ही पुर्तगाल ने बराबरी कर ली। जोआओ कैंसेलो ने जोरदार शॉट लगाकर स्कोर 1-1 कर दिया। निर्णायक गोल रामोस ने किया। जोआओ फेलिस ने गोल की ओर हेडर के जरिए गेंद पहुंचाई, जिसे रामोस ने अपने पैर के पिछले हिस्से से गोल में डाल दिया। पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस ने कहा, ‘नॉर्वे को हराने के लिए काफी



तकनीकी गुणवत्ता की जरूरत होती है। हमने डेनमार्क के खिलाफ जैसा प्रदर्शन किया था, वैसा प्रदर्शन किए बिना जीत हासिल की, लेकिन महत्वपूर्ण बात जीत और क्वालीफिकेशन थी। मुझे इस टीम पर काफी भरोसा था, लेकिन शायद मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि हम अपने पहले चार मैचों में चार जीत दर्ज कर लेंगे।’

पुर्तगाल की जीत हालांकि प्रॉसिस्को कॉसेइसाओ के लाल कार्ड के कारण कुछ फीकी रही। मैच खत्म होने से चार मिनट पहले उन्हें दूसरा पीला कार्ड मिला। पीला कार्ड मिलने के बाद उन्होंने रेफरी की ओर ज़्यागात्मक अंदाज में अंगूठा दिखाया, जिसके तुरंत बाद उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया गया। कार्डिफ में वेल्स के गोलकीपर डैनी वार्ड ने डेनमार्क को रोकने के लिए कई शानदार बचाव किए, लेकिन 75वें मिनट में

बाक्का टोपोला, सर्बिया। आयरलैंड की

पुरुष फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने इजराइल के खिलाफ नेशंस लीग मुकाबले से पहले एक बार फिर काली पट्टी बांधी और इजराइल के राष्ट्रगान के दौरान सिर झुकाकर गाजा में इजरायल की कार्रवाई के विरोध का संकेत दिया। इसके बाद दोनों टीमों के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इजराइल के खिलाड़ियों ने भी काली पट्टी पहनी। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में इजराइल में हुए हमलों में मारे गए लोगों की याद में ऐसा किया। इजराइल के कप्तान डोर पेरेट्ज की पट्टी पर ‘7.10’ लिखा था।

आयरलैंड के नियमित कप्तान डारा ओ’शे अपनी पत्नी के साथ बच्चे के जन्म के समय मौजूद रहने के लिए टीम से अलग थे, इसलिए गोलकीपर कैओमिन केलेहर ने कप्तानी की। केलेहर ने मैच से पहले रेफरी और उनके एक सहायक से हाथ मिलाया, लेकिन इजराइल के कप्तान पेरेट्ज से हाथ मिलाने से जानबूझकर परहेज किया। केलेहर ने पिछले सप्ताह हंगरी के डेब्रेसेन में खेले गए पहले मुकाबले में ओ’शे द्वारा अपनाए गए कप्तान को दोहराया। उस मैच में ओ’शे ने इजराइल के कप्तान मैंनोर सोलोमन से हाथ नहीं मिलाया था। आयरलैंड ने वह मुकाबला 3-0 से जीता था और तीनों गोल पहले हाफ में किए थे। रविवार के मुकाबले के लिए सोलोमन को शुरुआती एकादश से बाहर रखा गया और वह बेंच पर रहे। इजराइल के फारवर्ड सईद अबू फरची भी टीम में लौटे, जो 25 सितंबर को ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1-3 की हार के दौरान गोल का जश्न मनाने के बाद लाल कार्ड मिलने

वैभव बहुत समझदार खिलाड़ी हैं, उन्हें बस मौके का आनंद लेकर सर्वश्रेष्ठ देना है: अभिषेक शर्मा

नई दिल्ली। आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के अहम खिलाड़ियों में शामिल अभिषेक शर्मा नए घरेलू सत्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के साथ एक और खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने को तैयार हैं। जियोस्टार के कार्यक्रम ‘फॉलो द ब्लूज: जेन-नेवस्ट अभिषेक’ में अभिषेक ने एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट तक जीत की लय बनाए रखने, युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ बातचीत और अपने स्वाभाविक खेल को खेलने के लिए टीम प्रबंधन से मिले समर्थन पर विस्तार से बात की। अभिषेक ने आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप की जीत के बाद अगले विश्व कप में भी उसी सफलता को दोहराने और जीत की लय बरकरार रखने को लेकर कहा, ‘क्रिकेट में जब मैं आया था, तो 24 साल का था, अब मैं 26 साल का हूं। एक युवा क्रिकेटर के रूप में अनुभव से कहते हैं कि अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, यह सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है कि अभी भी आसान है, लेकिन उस चीज को आदत बनाना और बार-बार उसे दोहराना, प्रक्रिया को एक जैसा बनाए रखना, एक खिलाड़ी के

रूप में आसान नहीं है। अगर टीम का माहौल ऐसा हो कि हर कोई एक-दूसरे के लिए प्रदर्शन करना चाहता हो, भारत को जीत दिलाना चाहता हो, दबदबा बनाना चाहता हो, तो मुझे लगता है कि यह एक आदत बन जाती है और निश्चित रूप से इससे मदद मिलती है।’

युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ अपनी बातचीत और उन्हें सहज महसूस कराने को लेकर अभिषेक ने कहा, ‘वह बहुत समझदार खिलाड़ी हैं। वह वैसे नहीं हैं जैसे हम 15 साल की उम्र में हुआ करते थे या कोई और होता है, क्योंकि वह पहले ही दो-तीन साल से उस क्रिकेट सेटअप का हिस्सा हैं। इसलिए उन्हें पता है कि क्या, कहाँ और कितना अभ्यास करना है। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अनुभव के साथ वह इन चीजों को और सीखेंगे। टीम में हम एक-दूसरे के साथ, सभी साथी खिलाड़ी चर्चा करते हैं कि हम उन्हें कैसे अधिक सहज महसूस करा सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया है और वह यहां के हकदार हैं। इसलिए मुझे भी लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें महसूस कराऊं कि हम सभी, उनके बड़े भाई, उनके लिए यहां हैं।

आयरलैंड फुटबॉल टीम ने फिर पहनी काली पट्टी, इजराइल से हाथ मिलाने से किया इनकार



के कारण निर्बंधित थे। हालांकि, उन्हें इस मैच में खेलने का मौका नहीं मिला।

मैच का पहला गोल आयरलैंड ने किया। 39वें मिनट में पेरेट्ज द्वारा जिमी डन पर किए गए फाउल के बाद ट्रॉय पैरट ने पेनल्टी को गोल में बदलकर आयरलैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। पहले हाफ के बाद खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे, तभी दोनों पक्षों के बीच साइडलाइन पर बहस भी हुई। दूसरे हाफ की शुरुआत से पहले पेरेट्ज ने अपनी जर्सी के पिछले हिस्से को गर्दन के ऊपर उठाया, जिससे उस पर बना इजराइल का झंडा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। खेल शुरू होने के दो मिनट बाद उन्होंने करीब से गोल कर इजराइल

को 1-1 की बराबरी दिला दी। दूसरे हाफ में इजराइल के स्थानापन्न खिलाड़ी ओमरी गैंडेलमैन और ऑस्कर ग्लूख ने गोल के दाहिने पोस्ट पर गेंद मारी। मुकाबले के दौरान कुछ कड़े टैकल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता दिखा, जिस पर रेफरी जुआन मार्टिनेज सुनुएरा को लगातार नजर रखनी पड़ी। यह मुकाबला मूल रूप से डबलिन में खेला जाना था, लेकिन व्यापक बहिष्कार की मांगों के बाद आयरिश फुटबॉल संघ ने जून में इसे ‘परिचालन कारणों’ का हवाला देते हुए तटस्थ स्थान पर कराने का फैसला किया। संघ ने यह भी कहा था कि मुकाबला बिना दर्शकों के खेला जाएगा।

ब्रेसवेल न्यूजीलैंड क्रिकेट के कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर, निक केली को मिला पहला राष्ट्रीय अनुबंध

वेलिंगटन,एजेंसी। न्यूजीलैंड के

ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल 2026-27 सत्र के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट के केंद्रीय अनुबंध से हटकर कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर लौटेंगे। इससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने का अवसर हासिल करने की अनुमति मिलेगी। ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के कैजुअली कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की सूची में फिन एलन, मार्क चैपमैन, लॉकी फर्ग्युसन, एडम मिलने और टिम सोफर्ट के साथ शामिल होंगे। 35 वर्षीय ब्रेसवेल केंद्रीय अनुबंध में न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय अनुबंध मिला है।

ब्रेसवेल ने कहा कि वह न्यूजीलैंड के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में खेलने को लेकर उत्साहित हैं। ब्रेसवेल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट ने हवाले से कहा, ‘मेरे करियर के इस पड़ाव पर यह अवसर हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट का समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में, जो सिर्फ सीमित ओवरों का क्रिकेट खेलता है, यह ऐसा अवसर था जिसे छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अब भी ब्लैककेप्स के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और आगामी भारत दौरे तथा भविष्य की सीमित ओवरों की

सीरीज में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हूं। मेरी नजरें अगले सत्र से शुरू होने वाली एनजेड20 प्रतियोगिता में खेलने के अवसर पर भी पूरी तरह टिकी हुई हैं। केली ने मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था और अब तक आठ वनडे तथा सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। इस साल की शुरुआत में चोटिल टॉम लैथम की जगह उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी भी की थी। केली हाल ही में लीसेस्टरशायर के साथ अपना कार्यकाल पूरा करके लौटे हैं, जहां उन्होंने सभी प्रारूपों में 950 रन बनाए। उन्होंने मिडिलसेक्स के खिलाफ वनडे कप फाइनल में अपना छठा लिस्ट-ए शतक भी लगाया। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि घरेलू क्रिकेट में केली की निरंतरता ने उन्हें राष्ट्रीय अनुबंध दिलाया है। वाल्टर ने ओटागो में दो सत्रों के दौरान केली को कोचिंग भी दी है। वाल्टर ने कहा, ‘निक पिछले कई सत्रों से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं और यह उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है कि करियर के इस पड़ाव पर उन्हें अपना पहला अनुबंध मिला है। उन्होंने कहा, ‘निक जैसे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में थोड़ा देर से लाने के निश्चित रूप से कुछ फायदे हैं। खिलाड़ी इस समय तक अपने खेल को बेहतर तरीके से समझ चुका होता है और दबाव में प्रदर्शन करने के लिए खुद पर भरोसा कर सकता है।

एक नजर

वाणिज्य दूतावास बंद करने के जवाब में 27 इजराइली राजनयिकों को निकाल सकता है ब्रिटेन

लंदन। ब्रिटेन ने कथित तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर पूर्वी यरूशलम स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को बंद किया गया तो लंदन में तैनात 27 इजराइली राजनयिकों को निष्कासित किया जा सकता है। यह दावा इजराइली मीडिया को एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल में ब्रिटेन के राजदूत साइमन वॉल्टर्स ने इजराइली अधिकारियों तक यह संदेश पहुंचाया है। कथित तौर पर ब्रिटेन ने संकेत दिया है कि वाणिज्य दूतावास में कार्यरत प्रत्येक ब्रिटिश राजनयिक को सेवाएं समाप्त किए जाने के बदले एक इजराइली राजनयिक को निष्कासित किया जा सकता है। इजराइल दूतावास ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। वहीं, ब्रिटिश सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

लंदन में इजराइली दूतावास पर हमले की साजिश रचने वाले को उम्रकैद

लंदन। लंदन स्थित इजराइली दूतावास में घुसकर चाकू से हमला करने की कोशिश करने वाले कुवैती नागरिक अब्दुल्ला अलबद्री को अदालत ने उअकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सोमवार को आतंकवादी कृत्य के मामले में आरोपित को 20 वर्ष जेल में रखने का आदेश दिया है। 34 वर्षीय अलबद्री ने अप्रैल 2025 में पश्चिमी लंदन के केमिंग्टन स्थित इजराइली दूतावास की सुरक्षा घेरे को पार करने की कोशिश की थी। वह दो चाकूओं के साथ दूतावास की बाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तभी वहां तैनात सशस्त्र पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि अलबद्री ने दूतावास के स्थान की पहले से जानकारी जुटाई थी। उसके पास एक कथित 'सुसाइड नोट' भी मिला था। जांच में उसके मोबाइल फोन से दूतावास के स्थान और सुसाइड से जुड़े शब्दों की खोज किए जाने की जानकारी सामने आई। अभियोजन के अनुसार, अलबद्री इजराइल की गाजा में करंवाई के प्रतिशोध में दूतावास को निशाना बनाना चाहता था। हालांकि, अलबद्री ने अदालत में आतंकवादी हमला करने की तैयारी से इनकार किया था और कहा था कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दूतावास गया था। उसने चाकूओं को निजी सुरक्षा के लिए रखने की बात कही थी।

नाइजीरिया में 32 लोगों को ले जा रहा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त

लागोस। नाइजीरिया के दक्षिण-पश्चिमी ओडो प्रांत में सोमरारा के 32 लोगों को ले जा रहा एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 25 यात्री और सात चालक दल के सदस्य सवार थे। हादसे के बाद मलबा तटीय शहर इबोकाडा में नौसैनिक अड्डे के पास मिला। अधिकारियों ने तत्काल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है। नाइजीरिया के विमान मंत्री फेस्टस कीयामो के अनुसार, विमान बेनिन से लागोस की ओर जा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से सुरुह करीब 9:13 बजे संपर्क टूट गया। रेडियो के जरिए संपर्क बहाल करने के सभी प्रयास विफल रहने के बाद विमान के लापता होने की सूचना दी गई। बाद में अधिकारियों को विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली और उसका मलबा इबोकाडा स्थित नौसैनिक अड्डे के पास खोज लिया गया। नाइजीरियाई वायुसेना ने तत्काल खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया है। वायुसेना के अनुसार, विमान नियमित मिशन पर बेनिन से लागोस जा रहा था। विमान की पहचान टेल नंबर एएनजीआर 931 वाले सैन्य विमान के रूप में की गई है। फिलहाल हादसे के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है।

आईसीसी ने दो तालिबानी नेताओं के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट किए सार्वजनिक

द हेग। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंडजादा और तालिबान के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हकानी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट सार्वजनिक कर दिए हैं। दोनों के खिलाफ वारंट जुलाई 2025 में जारी किए गए थे, जिन्हें अब सार्वजनिक किया गया है। आईसीसी के अनुसार, प्री-ट्रायल चैंबर-2 ने दोनों के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उनके ऊपर मानवता के खिलाफ अपराध के तौर पर उत्पीड़न में कथित भूमिका के लिए कार्रवाई की है। आरोपों में लड़कियों/महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर उत्पीड़न तथा तालिबान को नीतियों से असहमत रखने वाले या महिलाओं के समर्थक माने जाने वाले लोगों का राजनीतिक आधार पर उत्पीड़न शामिल है। अदालत के मुताबिक, संबंधित अपराध अफगानिस्तान में तालिबान के अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद किए जाने का आरोप है, जो जनवरी 2025 तक जारी रहे। आईसीसी ने कहा है कि उसके पास दोनों नेताओं के कथित आपराधिक जिम्मेदारी मानने के लिए उचित आधार हैं।

काला सागर में जहाज में लगी आग, दो की मौत, चालक दल के 11 लोगों का रेस्क्यू



बुखारेस्ट। रोमानिया के पास काला सागर में एक जहाज में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक दल के 11 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह हादसा देश के क्षेत्रीय जल से बाहर हुआ और आग लगने के बाद जहाज के दुबने की स्थिति में होने की जानकारी है। रोमानियाई गृह मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवारों में चालक दल के 11 सदस्यों को बचा लिया गया। नौसेना प्राधिकरण ने हादसे में शामिल पोत की पहचान 'रॉयड ममाडोव' के रूप में की है। आग लगने के कारण के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। रोमानियाई मीडिया के अनुसार जहाज तुर्किये का था और उस पर अनाज लदा हुआ था। हादसा रोमानियाई ऊर्जा कंपनी ओएमपी पेट्रोम के संचालन वाले एक तेल प्लेटफॉर्म के पास हुआ। जहाज सेंट किट्स एंड नेविस के इंडोनेसिया के तहत संचालित हो रहा था और इटली के रावेन्ना की ओर जा रहा था। उपलब्ध पोत संबंधी जानकारी के अनुसार, इसका पिछला बंदरगाह यूक्रेन का इन्माइल था। रोमानिया नाटो का सदस्य है और यूक्रेन के साथ उसकी करीब 614 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से जहाजों के आसपास काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा संपर्की घटनाएं बढ़ी हैं।

ख्वाजा आसिफ बोले- पीटीआई नेता बुलेट प्रूफ सरकारी गाड़ियों में 'चूहों की तरह छिपे'



इथियारों से लैस काफिलों में घूम रहे हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर, सरकारी संसाधनों और इथियारों से लैस जुलूसों का इस्तेमाल अदालत के आदेशों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने सवाल किया कि अगर अदालत के आदेशों का ही उल्लंघन हो रहा है, तो पीटीआई और सरकार के बीच किफाी भी समझौते का सम्मान किए जाने की क्या गारंटी होगी। आसिफ ने यह भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर सभी पक्षों की सहमति और सम्मान था, लेकिन पीटीआई इसे मानने की तैयार नहीं है। उधर, खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत में गांधी चौक से प्रांत के मुख्यमंत्री मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी ने मार्च शुरू कर दिया है। पीटीआई महासचिव सलमान अकसर राजा ने रिविजर का दावा किया कि रात भर चली बातचीत के नाकाम होने की मुख्य वजह संघीय सरकार की यह जिद थी कि खैबर पख्तूनख्वा में उसने जो आतंकवाद-

विरोधी एकतरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार अपनी कार्रवाई राजा ने 'एक्स' टीवी पर टीटीपी नेता अपने अडिग रहे कि ऐसा संसदीय सहमति पर हो सकता है। सलाह-मशविरा और फैसला किया जा सकता है। इराक में पीपीपी के वे वकील हुमायूँ खान ने सरकार को मन्थेदों की सुलझाने का राजनीतिक सुलह का दावा किया कि टकराव का समाधान और बढ़ेगी। रिविजर ने कहा कि पीपीपी नेता ने कहा कि लोग लंबे समय तक रिविजर को जाम करने और अनिश्चितता का बोझ

काठमांडू में चर्च की फंडिंग से संचालित संस्था 'भूणका आवाजहरु' में फल-फूल रहा नवजात को गोद लेने का अवैध धंधा

काठमाडौं काठमाडौं में चर्च की फर्डिग सं संचालित 'भूणका आसवाजहरू' संस्था के बारे में सामनवीखेज खुलासा हुआ है। आरोप है कि 18 से 22 वर्ष की युवतियों को गर्भवती होने की मजबूर किया जाता है। यही नहीं, उनके नवजात बच्चों को गैरकानूनी तरीके से धर्मपुत्र-धर्मपुत्री के रूप में दूसरे परिवारों को सौंपा जाता है। जांच में चर्च और इस संस्था के पदाधिकारियों के इस अवैध गतिविधि में शामिल होने की बात सामने आई है।

बताया गया है कि गर्भवती होने के बाद जो युवतियाँ अपने चाहती थीं कि वह बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती, उन्हें संस्था के शेल्टर में रखा जाता था। वहाँ बच्चे को जन्म देने के बाद उसके नवजात को कथित तौर पर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना दूसरे लोगों को सौंप दिया जाता था। नेपाल के प्रचलित कानून के अनुसार नेपाल के भीतर किसी बच्चे को धर्मपुत्री या धर्मपुत्री के रूप में देने के लिए जिला अदालत की अनुमति अनिवार्य है। अदालत कानूनी शर्तों की जांच के बाद ही बच्चे को गोद देने की अनुमति दे सकती है। जांच के अनुसार, अमेरिकी संस्था 'लाइफ

विरोधी एकतरफा कार्रवाई शुरू की, उसे प्रांतीय सरकार अपनी कार्रवाई के तौर पर स्वीकार करे। राजा ने 'एक्स' पर कहा कि पीटीआई-टीडीपी नेता अपने उस सैद्धांतिक रुख पर अडिग रहे कि ऐसा संघीय और राज्य सरकार की सहमति पर हो सकता है। इसे विधासभा में सलाह-मशविरा और सहमति के बाद स्वीकार किया जा सकता है। इस बीच पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के केंद्रीय महासचिव मोहम्मद हुमायूँ खान ने सरकार और पीटीआई के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए संवाद के जरिए राजनीतिक सुलह का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि टकराव से राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ेगी। रविवार को पेशावर में जारी बयान में पीपीपी नेता ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग लंबे समय तक विरोधी की राजनीति, सड़कों को जाम करने और लगातार राजनीतिक अनिश्चितता का बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि

ऐसी घटनाओं का सीधा असर आम नागरिकों, व्यापारियों और कारोबारी समुदाय पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले रखना लोकांतिक राजनीति का मूल तत्व और एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं को व्यक्तिगत और पार्टीगत मतभेदों से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों के समाधान को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनानी चाहिए। पीपीपी नेता ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून-व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी जन-सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर तत्काल राजनीतिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और प्रभावी कामकाजी संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों का मजबूती मिल सकती है और राजनीतिक व प्रशासनिक स्थिरता में योगदान मिल सकता है।

नेपाल में अत्यावश्यक अभियान को छोड़कर बाढ़ खोज एवं बचाव कार्य फिलहाल स्थगित

काठमांडू, एजेसी। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी-त्रिशुली बाढ़ के बाद जारी खोज एवं बचाव अभियान को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालाँकि, अत्यावश्यक खोज कार्य जारी रहेगा। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन परिषद की 21वाँ बैठक में संबंधित निकायों को अत्यावश्यक खोज कार्य के साथ-साथ पुर्ननिर्माण और पुर्नस्थापना का काम तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

यह निर्णय जिला सुरक्षा समिति, जिला आपदा प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण को कार्यकारी समिति की सिफारिशों और मौके पर किए गए निरीक्षण के आधार पर लिया गया। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं निकायों से प्राप्त 504 योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 5 खर्ब 59 लाख 17 करोड़ 72 लाख 27 हजार नेपाली रुपये के बजट की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेजने का निर्णय लिया गया। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, 2077 के तहत स्वीकृत इन योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। जिन परियोजनाओं की लागत का अनुमान अभी तक नहीं हुआ है या जिनका प्राथमिकता निर्धारण बाकी है, उनको जिनका मिलने के बाद आवश्यक बजट व्यवस्था के लिए वित्त मंत्रालय को सिफारिश करने का निर्देश राष्ट्रीय आपदा जोखिम



न्यूनीकरण तथा प्रबंधन है। बैठक में प्रधानमंत्री प्रबंधन का काम संघी सरकारों के समन्वय से पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना के समन्वय के साथ आगे में विपक्षी दल, नेपाली के नेता तथा बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्रियों आश्वासन दिया। परिषद



पूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। ब्रैडक ने प्रधामंत्री शाह ने कहा कि आपदा प्रबंधन का काम संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के समन्वय से किया जा रहा है और अब पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना का काम भी इसी समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इस कार्य में विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता तथा बागमती, गंडकी, मधेश और कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। परिषद ने भी कोशी-त्रिशूली बाढ़ तथा मानसून से संबंधित आपदाओं में हुए जन-धन की क्षति पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के प्रति भावपूर्ण शुष्कजलि और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। साथ ही, कठिन परिस्थितियों में खोज, बचाव राहत और पुनर्स्थापना कार्य में जुटे सुरक्षकर्मियों, जनप्रतिनिधियों, राष्ट्रसेवकों, निज क्षेत्र, स्वयंसेवकों और पत्रकारों के साथ-साथ समन्वय करने वाले दाता देशों और विकास साझेदारों के प्रति परिषद ने आभार व्यक्त किया।

बाढ़ तथा मानसूरी से संबंधित आपदाओं में ह
जन-धन की क्षति पर गहरा दुःख व्यक्त करते हु
मृतकों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शोक
संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की
साथ ही, कठिन परिस्थितियों में खोज, बचाव
राहत और पुनर्स्थापना कार्य में जु
सुशास्त्रकार्मियों, जनप्रतिनिधियों, राष्ट्रसेवकों, नि
क्षेत्र, स्वयंसेवकों और प्रचक्रारों के साथ-साथ
सहयोग करने वाले दाता देशों और विकास
संज्ञेदारों के प्रति परिपद ने आभार व्यक्त किया

नेपाल राष्ट्र बैंक ने विदेशी मुद्रा भुगतान की सीमा बढ़ाई, भारत में इलाज से लेकर भुगतान तक कई नियमों में बदलाव

काठमांडू, एंजेसी। नेपाल राष्ट्र बैंक ने विदेशी मुद्रा भुगतान और सटही (विनिमय) से जुड़े मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करते हुए व्यवसायियों और सेवाप्राप्तकों के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान को विभिन्न सीमाएं बढ़ा दी हैं। राष्ट्र बैंक के विदेशी विनिमय प्रबंधन विभाग ने एकीकृत परिपत्र में संशोधन कर आयात, सेवा भुगतान, विमान के इंजन व पार्ट्स, सैटेलाइट सेवा, भारत में किए जाने वाले भुगतान सहित कई कारोबारों में विदेशी मुद्रा भुगतान को सीमा बढ़ाई है।

भारत स्थित संस्थाओं और कंपनियों से विभिन्न सेवाएं लेने के लिए नेपाली तथा विदेशी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले भुगतान की सीमा भी बढ़ाई गई है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर प्रति लेनदेन 60 लाख भारतीय रुपये तक की सटही सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। पहले यह सीमा 40 लाख भारतीय रुपये थी। संशोधित व्यवस्था के तहत नेपाली नागरिकों को विदेश में इलाज के लिए अब सालाना 30 हजार अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा सटही सुविधा मिलेगी। इससे पहले यह सीमा 16 हजार डॉलर थी। राष्ट्र बैंक की जारी संशोधित एकीकृत निर्देशिका के अनुसार, विमान के इंजन या पार्ट्स को विदेश में ले जाकर मरम्मत कराने के लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले अग्रिम भुगतान की सीमा 1 लाख डॉलर से बढ़ाकर 5 लाख डॉलर कर दी गई है। राष्ट्र बैंक ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा सकने वाली वार्षिक सटही सुविधा की सीमा भी 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार अमेरिकी डॉलर कर दी है। विदेशी सेवा प्रदाताओं से समझौता कर सैलैन्ड्राट सेवा किएार पर लेने वाली नेपाली दूसरंचार कंपनियों के लिए भी सालाना सेवा



शुल्क भुगतान की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख डॉलर कर दी गई है। नियामक निकाय से समझौते, सहमति या सटही की सिफारिश प्राप्त कारोबार में प्रति लेनदेन सटही सुविधा की सीमा भी 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार डॉलर कर दी गई है।

सेवा आयतन के लिए अग्रिम भुगतान करते समय विदेशी बैंक की बैंक गारंटी जरूरी होने की सीमा भी बढ़ाई गई है। पहले 15 हजार डॉलर से अधिक के अग्रिम भुगतान पर बैंक गारंटी जरूरी थी। अब यह

सीमा 30 हजार डॉलर कर दी गई है।

से प्राप्त रकम का इस्तेमाल आयात भुगतान, सीमा भी बढ़ाई है। तीसरे देशों के माल से 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार अमेरिकी डॉलर तक का माल ले आयात करने पर बैंक गारंटी के मामले में यह रुकाने से बढ़ाकर 60 लाख भारतीय रुपये कर दिया गया है।

निर्यात से होने वाली आय का इस्तेमाल माल के मालिकों में करके वापस आयात की ओर संचालित करने के लिए व्यवसायियों को सटही संभावना है। राष्ट्र बैंक ने पर्यटन

सीमा 30 हजार डॉलर कर दी गई है। राष्ट्र बैंक ने निर्यात से प्राप्त रकम का इस्तेमाल आयात भुगतान में करने की सीमा भी बढ़ाई है। तीसरे देशों के मामले में यह सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार अमेरिकी डॉलर कर दी गई है। भारत के मामले में यह सीमा 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख भारतीय रुपये कर दी गई है। इससे निर्यात से होने वाली सीमा का इस्तेमाल आयात भुगतान में करने वाले व्यवसायियों को सुविधा मिलने की संभावना है। राष्ट्र बैंक ने पर्यटन कारोबार से जुड़े

भुगतान में भी कुछ सहूलियत दी है।

विशेषों में पर्यटन सेवाएं बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त टैवल और टूर एजेंसियां विदेशी एजेंटों को भुगतान करके सप्ताह संबंधित टैवल/टूर एजेंट के नाम पर विदेशों पर प्रसार प्रक्रम तथा बिल-बिजक के आधार पर भुगतान कर संकेतों। सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक कृषि विनिमय, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली नेपाली फर्मों तथा कंपनियों को विदेशी संरक्षण लाने के उद्देश्य से 'क' वर्ग के बैंक विदेशी मुद्रा में बैंक गारंटी या स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर सकते हैं। ऐसी गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट ऋण के प्रभावशील मूलधन राशि और अवधि कायम रहने तथा प्रभावी रहेगा। विदेशी ऋण से जुड़े अन्य प्रावधानों नेपाल राष्ट्र बैंक के विदेशी निवेश तथा विदेशी ऋण प्रबंधन विनियमवली के अनुसार लागू होंगे। विदेशी में ऑनलाइन सूचना निर्गत कर विदेशी मुद्रा आय अर्जित करने वाली कार्डधारकों के लिए भी विदेशी मुद्रा रखने की सीमा बढ़ाई गई है।

पहले कार्ड में अधिकतम 5 हजार डॉलर रखने का अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर 10 हजार डॉलर कर दिया गया है। इस तरह, सेवा निर्यात से विदेशी मुद्रा आयात करने वाले कार्डधारक विदेशों में वस्तु और सेवाओं खरीदने के लिए सालाना 10 हजार डॉलर तक की सटर्ही सुविधा इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले यह सीमा केवल 500 डॉलर थी। इस संशोधन के जरिए नेपाल राष्ट्र बैंक ने विदेशी मुद्रा से जुड़े कई भुगतान और सटर्ही प्रावधानों में सीमा बढ़ाकर व्यवसाय, सेवा आयात-निर्यात, विदेशी इलाज, पर्यटन, विमानन, दूरसंचार और विदेशी ऋण से जुड़े कारोबार को आर्थिकाक्षत अधिक सुविधा देने के व्यवस्था की है।

एक नजर

भाजपा उम्मीदवार दिनेश आर्य राज्यसभा के लिए मंगलवार को दाखिल करेंगे नामांकन

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा

उम्मीदवार दिनेश आर्य मंगलवार को विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद जताई है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने सोमवार को बताया कि राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद दिनेश आर्य ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा समेत प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी की विधि टीम ने नामांकन से संबंधित औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि दिनेश आर्य पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और लंबे समय तक संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संचाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आर्य जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और कुमाऊं क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने में उनका योगदान रहा है। भट्ट ने पार्टी नेतृत्व के निर्णय पर कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों में उत्साह होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को उम्मीद है कि दिनेश आर्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होंगे।
मनवीर चौहान के अनुसार, पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार सुबह 10 बजे भाजपा के सभी विधायक विधानसभा में एकरत्र होंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे दिनेश आर्य नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

कुंम मेला 2027: 32 सेक्टरों में 13 हजार शौचालय, सैनिटेशन की एकीकृत कार्य योजना तैया

हरिद्वार। कुंभ मेला 2027 में सफाई और सैनिटेशन की व्यापक व्यवस्था के लिए शासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा ने सोमवार को मेला नियंत्रण भवन में कुंभ क्षेत्र के नगर निकायों, जिला पंचायतों और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने एकीकृत सैनिटेशन कार्ययोजना को एक सप्ताह में अंतिम रूप देकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि सफाई व्यवस्था की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग के डैशबोर्ड पर सभी निकायों को मैप किया जाएगा। कार्ययोजना में मेला से पहले और बाद की व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। मानव संसाधन, उपकरण और सामग्री की तैयारी अभी से सुनिश्चित की जाए। सैनिटेशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर आयुक्त नंदन कुमार को समन्वय अधिकारी बनाया गया है। सभी विभाग अपनी प्रगति रिपोर्ट उन्हें देंगे। नगर आयुक्त ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि कुंभ क्षेत्र के 32 सेक्टरों में 13,865 टॉयलेट सीट, 8,065 एनआरपी मूत्रालय और 4,840 डस्टबिन लगाए जाएंगे। सफाई के लिए 493 वाहनों का उपयोग होगा। सीवरेज निस्तारण के लिए 6 एफएसटीपी का उपयोग किया जाएगा। दिसंबर से सफाई कर्मियों की तैनाती शुरू होगी। बैठक में मेलाधिकारी सोनिका, आजीजी कुंभ योगेन्द्र रावत, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित समेत चार जिलों के अधिकारी मौजूद रहे।

घर में घुसकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुटी पुलिस

अमेठी। अमेठी जिले के रामगंज थाना क्षेत्र में आधी रात घर में घुसकर 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगने से सनसनी फैल गई। आरोप है कि वारदात के दौरान आरोपी ने किशोरी की मां को कड़ा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार घटना तीन अक्टूबर की रात करीब 1:30 बजे की है। जब गांव का अमन गुप्ता पुत्र मनोज कुमार गुप्ता कथित रूप से घर में घुस आया। आरोप है कि उसने 15 वर्षीय किशोरी के साथ जबर्न दुष्कर्म किया। किशोरी की आवाज सुनकर उसकी मां ने दरवाजा खोला तो आरोपी ने हाथ में कड़ा लिए सामने खड़ा था। आरोप है कि उसने घटना किसी को बताये पर जान से मारने की धमकी दी और धक्का देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी के जाने के बाद उसका मोबाइल फोन घर में पड़ा मिला। किशोरी के कपड़ों पर खून के निशान मिलने की बात भी तहरीर में कही गई है। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी रामराज कुशवाहा ने सोमवार को बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को वर्ष 2026 का चिकित्सा का संयुक्त नोबेल पुरस्कार

स्टॉकहोम,एजेंसी। कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को प्रकाश-सक्रिय आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 2026 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की सोमवार को घोषणा की गई। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने इसका ऐलान किया। पुरस्कार तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

नोबेल असेंबली के अनुसार इन वैज्ञानिकों की खोजों ने न्यूरोसाइंस के एक नए युग की नींव रखी है। इस वर्ष नोबेल पुरस्कार की राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना (लगभग 11.51 करोड़ रुपये) है। यह राशि तीनों विजेताओं के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति-पत्र और पदक भी प्रदान किया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों को ‘प्रकाश-सक्रिय आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स से संबंधित खोजों’ के लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है, जिसमें प्रकाश की सहायता से तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। इसके विपक्ष से तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है। पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनलरोडोप्सिन प्रोटीन की खोज की। इसके बाद कार्ल डाइसेरोथ ने इस प्रोटीन को तंत्रिका कोशिकाओं के लिए प्रकाश-नियंत्रित

विद्यार्थी तकनीक को शक्ति और विवेक को मार्गदर्शक बनाएं : संतोष कुमार गंगवार

रांची,एजेेंसी। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह सोमवार को रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित हुआ। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान 207 सफल विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई, जबकि विभिन्न संकायों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले पांच मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशिष्ट अतिथि तथा उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं सेवानिवृत्त आईपीएस जीके गोस्वामी सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति राहुल पुरवार, रजिस्ट्रार डॉ. हेमेंद्र कुमार भगत सहित शिक्षक, अधिकारी, विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी समारोह में उपस्थित रहे।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक यात्रा का पड़ाव नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा की नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से तकनीक को अपनी शक्ति और विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल कानून, मानव गरिमा, नागरिक अधिकार और निजता का सम्मान करते हुए होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज

यूपी में 2100 से अधिक कैदीन बनीं आत्मनिर्भरता की ‘प्रेरणा’, दस हजार परिवारों का बनीं सहारा

लखनऊ,एजेेंसी। सरकारी दफ्तरों में आने-जाने वाले लोगों की रोजाना की आवाजाही अब ग्रामीण महिलाओं की कमाई का जरिया बन रही है। उत्तर प्रदेश में 2100 से अधिक प्रेरणा कैंटीन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए रोजगार और कारोबार का नया मंच बन चुकी हैं। इसके साथ ही आज ये दस हजार परिवारों का सहारा बन गई हैं। विकास भवन, कलेक्ट्रेट और ब्लॉक कार्यालयों (यूपीएसआरएलएम) के सहयोग से संचालित इस पहल के जरिये महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में कारोबार का अवसर मिल रहा है।

प्रेरणा कैंटीनों के लिए सरकारी कार्यालयों की रोजाना की फुटफॉल कारोबार का आधार बन रही है। कर्मचारियों और आगंतुकों की आवाजाही से कैंटीनों को स्थानीय ग्राहक मिल रहे हैं। इससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार के साथ कारोबार चलाने का अनुभव भी मिल रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए समूहों को दूर बाजार तलाशने के बजाय सरकारी परिसरों में ही कारोबार का मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रेरणा कैंटीनों का विस्तार विकासखंड स्तर तक होने से गांव के स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय स्तर पर कारोबार का अवसर मिल रहा है। सरकारी



सुरक्षा व्यवस्था के समने साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा सुरक्षा, वित्तीय अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग, डीपफेक, वॉयस क्लोनिंग, भ्रामक सूचनाओं और साइबर हमलों जैसी नई चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विश्लेषण क्षमता और निरंतर सीखने की आदत विकसित करनी होगी। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के किसी जिले या क्षेत्र की पहचान साइबर अपराध से नहीं जुड़नी चाहिए। उन्होंने युवाओं से इस क्षेत्र में अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग करते हुए साइबर अपराध की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में साइबर

अपराध, अपराध मनोविज्ञान, महिला एवं बाल सुरक्षा, वित्तीय अपराध, नशीले पदार्थों की रोकथाम, आपदा प्रबंधन और आधुनिक पुलिसिंग जैसे विषयों पर समाधानपरक शोध को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। साथ ही पुलिस प्रशासन, रक्षा संस्थानों, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत के साथ अकादमिक संबंध मजबूत करने तथा विद्यार्थियों को फील्ड ट्रेनिंग, इंटरैनिश और केस स्टडी के अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की आधारशिला पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर ने रखी थी। उनकी सादगी, कर्मठता और राष्ट्र सेवा की भावना विश्वविद्यालय के लिए प्रेरणास्रोत है।

इजराइल की प्रारंभिक जांच में फ्लाईदुबई के विमान को हाईजैक करने की कोशिश करने वाला को-पायलट ‘लोन वुल्फ’

तेल अवीव,एजेेंसी। इजराइल की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि फ्लाईदुबई के विमान को हाईजैक करने की कथित कोशिश शायद एक ‘लोन-वुल्फ’ हमला था। इजराइल के प्रचामंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को विमान के यात्रियों और फ्लाइट कैप्टन ने बताया कि बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट जब इजराइल के पास पहुंच रही थी, तब को-पायलट ने कथित तौर पर फ्लाइट कैप्टन को चाकू मारा और विमान को क्रैश करने की कोशिश की। सीबीएस न्यूज और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कैप्टन ने को-पायलट से लड़ते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद इजराइली यात्रियों और फ्लाईदुबई के स्टाफ के लोगों ने को-पायलट को दबोच लिया। फ्लाइट में मौजूद दो ऑफ ड्यूटी पायलटों ने विमान को अपने नियंत्रण में लेकर सऊदी अरब के तबुक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई।

को-पायलट अभी संयुक्त अरब अमीरात (यूईए) में हैं। वहां उससे इजराइल के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले सऊदी अधिकारियों ने भी उससे पूछताछ की। इजराइल ने जांच में शामिल होने के लिए अपने प्रतिनिधि यूईए भेजे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्वार को कहा कि ‘जो मैंने सुना है, उसके आधार पर’ हो सकता है कि को-पायलट का संबंध ईरान से हो। ट्रंप ने कहा, ‘हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। वे हमारे साथ बहुत खुलकर बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि जो मैंने सुना है, उसके आधार पर जवाब ‘हां’ है। इससे पहले नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि को-पायलट के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नेतन्याहू ने गुस्वार को कहा कि इजराइल को पता था कि को-पायलट इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था। उन्होंने कहा हमलावर ‘आत्मघाती’ था और जब क्रू के अन्य

जम्मू-कश्मीर घूमने गए पर्यटक दल की बस दुर्घटनाग्रस्त, पोटाशपुर की महिला की मौत

कोलकाता। पश्चिम मेदिनीपुर के जाहलदा से 65 लोगों के पर्यटक दल के साथ जम्मू-कश्मीर घूमने गई पोटाशपुर की एक महिला की बस दुर्घटना में मौत हो गई। मृतका की पहचान पोटाशपुर-दो प्रखंड के बड़इदा गांव निवासी यमुना ठाकुर (49) के रूप में हुई है। दुर्घटना में पूर्व मेदिनीपुर के 15 अन्य पर्यटक घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही शनिवार रात विधायक दिव्येंद्र अधिकारी सक्रिय हुए। प्रशासन के अनुसार, घायलों को वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है।

रविवार को पोटाशपुर-दो के बीडीओ, संयुक्त बीडीओ सहित प्रखंड प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मृतका के परिवार से मुलाकात कर हरसंभव सहयोग का आवासन दिया। परिवार के सदस्यों के जम्मू-कश्मीर जाने की व्यवस्था भी की गई है। सोमवार सुबह यमुना के बेटे समेत परिवार के चार सदस्य सियालदह से ट्रेन से जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना हो गए। यमुना के बेटे शुभंकर ने कहा, ‘दाह संस्कार के बाद शव को घर तक वापस लाने की आर्थिक क्षमता हमारे स्टडी के अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की आधारशिला पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर ने रखी थी। उनकी सादगी, कर्मठता और राष्ट्र सेवा की भावना विश्वविद्यालय के लिए प्रेरणास्रोत है।



सदस्यों और यात्रियों ने उसे काबू किया, तो वह चिल्लाया: ‘मुझे मार डालो, मुझे मार डालो।’ फ्लाइट के को-पायलट की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, हालांकि जांच से जुड़े कई सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि उसका नाम हमम अल-हमामी है।

सूत्रों के अनुसार, अल-हमामी ने कुछ समय के लिए ओमान एयर के लिए काम किया। यहां उसने नए पायलट की ट्रेनिंग शुरू की थी। सूत्रों ने बताया कि ओमान सरकार की निगरानी में पता चला कि वह कट्टरपंथी वेबसाइटें देखता था। इसके बाद ओमान एयर ने उसे ऑफिस से अटैच कर दिया। इसके बाद अल-हमामी ने इस्तीफा दे दिया। उसने 2024 के आसपास एयरलाइन छोड़ दी। सूत्रों से अलग होकर अकेले शिकार करता है, वैसे ही यह हमलावर भी पूरी योजना और हमला अकेले ही रचता है। हालांकि ऐसे हमलावर किसी संगठन के सीधे संपर्क में नहीं होते, लेकिन वे इंटरनेट, सोशल मीडिया या डाक वेब पर मौजूद किसी बड़े चरमपंथी समूह (आईएसआईएस या ख़त वर्रख्खादी संगठन) की कट्टरपंथी विचारधारा और प्रोपेगंडा से प्रभावित या प्रेरित जरूर होते हैं।

तमिलनाडु के मदुरांतकम और धारापुरम उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को मतदान, सार्वजनिक अवकाश घोषित

चेन्नई,एजेेंसी। तमिलनाडु के मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा।

दोनों सीटों पर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदाता अपने मतार्थिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान रविवार शाम छह बजे समाप्त हो गया। तमिलनाा वेत्रि कझगम (तवेक) के समर्थन वाले कम्युनिस्ट दलों ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग उम्मीदवार करने की सुविधा देना है। सरकार की ओर से जारी शासनादेश में 1881 के अधिनियम की धारा 25 की व्याख्या और केंद्रीय गृह मंत्रालय की आठ जून

चरण में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदान के दिन की तैयारियों में जुटे हैं।

उपचुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार ने 6 अक्टूबर को मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शासनादेश के अनुसार, इन विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान, सरकार के नियंत्रण वाले संस्थान और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सरकार ने इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे मतदाता कर्मचारी, जो पड़ोसी जिलों में कार्यरत हैं, उन्हें भी 6 अक्टूबर को वेतन सहित अवकाश देने का आदेश दिया गया है। इसका उद्देश्य संबंधित कर्मचारियों को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचकर मतार्थिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना है। सरकार की ओर से जारी शासनादेश में 1881 के अधिनियम की धारा 25 की व्याख्या और केंद्रीय गृह मंत्रालय की आठ जून

व्यवस्था की गई है। जम्मू के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से संपर्क कर मृत्यु प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के लिए सहयोग करने को कहा गया है। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, 19 सितंबर को पश्चिम मेदिनीपुर के जाहलदा से 65 लोगों का दल आराक्षित बस से कश्मीर घूमने के लिए रवाना हुआ था। दल में अधिकांश लोग एगारा महकमा क्षेत्र के रहने वाले थे। वापसी के दौरान शनिवार सुबह करीब 8:50 बजे श्रीनगर से जम्मू जाने के रास्ते में रामबन के मरग इलाके में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया गया है कि बस का ब्रेक फेल होने के बाद वह एक चट्टान से जा टकराई। दुर्घटना में बस में सवार यात्रियों को कम-अधिक चोटें आईं। स्थानीय पुलिस और सेना ने घायलों को बचाकर स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने यमुना ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स हैंडल पर लिखा कि रामबन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर से वह दुखी हैं। उन्होंने वहां के उपायुक्त से बात की और घायलों का इलाज कराने तथा उन्हें जल्द सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी रामबन के उपायुक्त मोहम्मद इलियास खान से बात की।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से

प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)

